04 - देश में पुल हादसों का सच,खोखली निगरानी

05 - विदेशी फंडिंग और सामाजिक विघटन का षड्यंत्र

06 - पत्रकारिता पर हमेशा संकट रहा है, संघर्ष पत्रकारों की नियती : मंत्री प्रहलाद पटेल

07 - सभी कलेक्टर्स सड़कों पर विचरण करने वाले...

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 17 जुलाई, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 278, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या एसआईआर हर किसी की नागरिकता को संदिग्ध बना देगा?

अरविंद मोहन

ख़बर है कि बिहार बीजेपी के सांगठनिक सचिव भिखू भाई दलसानिया ने राज्य बीजेपी के 23 पदाधिकारियों के साथ पटना में बैठक की और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर पर पार्टी के लोगों की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा। ऐसा इस अभियान से हो सकने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 26 याचिकाएँ दाखिल की गई हैं। उल्लेखनीय है कि किसी ने भी इस प्रक्रिया पर रोक की मांग नहीं की है। अदालत ने एक बार की सुनवाई में सरकारी वकील से कई बातों का स्पष्टीकरण मांगने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनाने में आधार कार्ड, पुराने मतदाता पहचान-पत्र और राशन कार्ड को भी विचार के लिए शामिल करने का सुझाव दिया जिन्हें चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए ज़रूरी 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया था। इसे ही लेकर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है।

आयोग और उसके समर्थन में बीजेपी के लोग यह कहते रहे हैं कि मतदाता का नागरिक होना जरूरी है और ये प्रमाणपत्र पुख्ता रूप से नागरिकता साबित नहीं करते। फिर फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड, इनकी सूची से 40 लाख फर्जी नाम निकाले जाने या कई जिलों में मतदाताओं की तुलना में आधार कार्ड की संख्या ज़्यादा होने जैसी दलीलें दी जाती रही हैं। और बात घूम फिर कर मतदाता बनाम नागरिकता की बहस और बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठ, हिन्दू-मुसलमान और 'इससे देश को होने वाले ख़तरे' पर आ गई है।

बीजेपी मानकर चलती है कि उसे मुसलमानों का वोट लगभग नहीं मिलता। विपक्ष अर्थात कांग्रेस और आरजेडी मुसलमान वोट को अपना आधार मानते हैं। उनका इसके लिए चिंतित होना एक तात्कालिक ज़रूरत है। और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाला विपक्ष इस बार शुरू से बहुत चौकस रहा है- शोर मचाने से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने तक। इसीलिए यह मसाला जल्दी चर्चा में आया और यह पूरी प्रक्रिया सबकी नजर में है। इसमें जब अजीत अंजुम जैसे कोई पत्रकार सूची नया करने वालों को बिना प्रशिक्षण मैदान में उतारने और इस प्रक्रिया में दोष की ख़बर देते हैं तो उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है।

बिहार ही क्यों, बंगाल भी इस सर्वेक्षण के सवाल पर अभी से गरमाने लगा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग और सरकार जल्दी-जल्दी यह काम निपटाने का अभियान चला रही है। इससे विपक्षी अभियान तो मद्धिम नहीं पड़ा है लेकिन लोजपा और जदयू जैसे सहयोगी दल उलझन में हैं और अब ख़बर है कि खुद बीजेपी भी नुक़सान को लेकर डरने लगी है।

अब इस प्रक्रिया का अंत तो मतदाता सूची के प्रकाशन, आपत्तियों के निपटान और कुछ मुकदमे-सुनवाई जैसी सामान्य विधि में ही होनी है। इस सघन अभियान से सूची पर कुछ भी बड़ा फर्क नहीं होगा। सारे नाम वापस आएंगे और नए नाम भी सुविधा से जोड़े जाएंगे। अगर कुछ हुआ है तो नागरिकता और हिन्दू-मुसलमान का मुद्दा राजनैतिक डिस्कोर्स में नए तरह से उठा है और इसके अपने नफा नुक़सान हैं। लेकिन असली नुक़सान आयोग और देश की उस बड़ी योजना को होने जा रहा है, जिसमें अगले साल तक देश के सभी मतदाताओं की पहचान और उनके फ़ोटो पहचान को नई तकनीक के माध्यम से मिलाकर पक्का रूप दे देना था। बिहार में जिस तरह से अप्रशिक्षित लोग फार्म भर रहे हैं, वे अपना काम दूसरे लोगों से करा रहे हैं, फार्म के साथ लगने वाले दस्तावेज और फ़ोटो में जिस तरह कई लापरवाही सुनाई दे रही है उससे साफ लगता है कि आयोग की तैयारी आधी-अधूरी है, उसने बहुत कम समय में यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, वह विपक्षी हंगामे के दबाव में है और संभवतः उससे भी ज़्यादा शासक दल के दबाव में काम कर रहा है। राजनैतिक हंगामे के बाद दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह नाम काटना और जोड़ना भी संभव नहीं होगा जो आरोप विपक्ष लगा रहा है।

और बात सिर्फ़ विपक्ष के आरोप या राहुल गांधी द्वारा चुनाव बीतने के काफी बाद दिए जाने वाले आंकड़ों भर की नहीं है। खुद आयोग के आँकड़े भी इस अभियान की मंशा और प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सामान्य ढंग यही रहा है कि हर साल डेढ़ से दो करोड़ नए मतदाता नई सूची में आ जाते हैं। नए वोटर बनने वाले लड़के-लड़कियों को जोड़ने और इस बीच दुनिया या शहर/गाँव छोड़कर नई जगह जाने वालों की गिनती घटाने के बाद मिली संख्या। पर इधर आबादी की वृद्धि दर में कोई बाद बदलाव नोटिस नहीं किया गया है लेकिन 2023 से मतदाता सूची का आकार 18 लाख घट गया है। जाहिर तौर पर इतने ज़्यादा नाम काटने की कोई वजह, या उनको दिए गए नोटिस या सुनवाई की ख़बर भी नहीं आई है। अर्थात् नाम अपनी तरफ़ से काट दिए गए और कोई वैधानिक औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई। इसी बिहार में फ़ॉर्म भरे जाने के बाद मांगे जाने पर भी कहीं से भी पावती दिए जाने की ख़बर नहीं है। हालाँकि संसद में सरकार ने पिछली बार मात्र तीन बांग्लादेशी लोगों के नाम मतदाता सूची में आने और पकड़े जाने की बात मानी थी।

लेकिन इसी हड़बड़ी, इसी तरह के दबाव और बिहार जितनी कम तैयारी के साथ अगर 'गहन पुनरीक्षण' किया जाता रहा तो यह सचमुच की शुद्ध सूची बनाने के घोषित उद्देश्य के खिलाफ ही जाएगा। सो एक बड़ा नुकसान तो इतनी उन्नत तकनीक और इतने साधनों की बर्बादी के बावजूद कोई लाभ हासिल न होना ही होगा। पर उससे भी ज्यादा मतदाता बनाम नागरिक का व्यर्थ का विवाद छेड़ने, मामले को सांप्रदायिक रंग देने, दोनों समुदायों में द्वेष बढ़ाने और नागरिकता के सवाल का मजाक बना देना होगा। असम में हम ऐसा उलझाव देख रहे हैं जो वर्षों से वैसे ही पड़ा है और हर चुनाव में इस्तेमाल होता है। अब अगर बिहार और फिर बंगाल में ऐसा हुआ तो देश का एक बड़ा हिस्सा खुद-ब-खुद एक जाल में फँसेगा जो हर किसी की नागरिकता को संदिग्ध बना देगा। और जैसा बीजेपी के प्रभारी पदाधिकारी को भी लग रहा है कि यह सवाल उसे लाभ देने की जगह घाटा दे सकता है तो मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चुनाव एजेंसी बनकर भी आयोग अगर इस तरह के फैसले करेगा, ऐसे काम करेगा तो उसकी मर्यादा और शक्ति दोनों का ह्रास होगा ही।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

मुझको मेरे डर ने रोका,
इसके बाद सफर ने रोका।
तुम्हे देखने ठहर गया था,
तेरे उसी असर ने रोका।
आना था तेरे दर तक पर,
मुझको गुजर बसर ने रोका।
फिर न सकेगा लौट यहां से,
कह कर यही डगर ने रोका।
इंतज़ार की रातें बीती,
उसके बाद सहर ने रोका।
नदी नहीं रुक पायी लेकिन,
उसकी एक लहर ने रोका।
अमृत ने तो जान निकाली,
पर बदनाम जहर ने रोका।

तुमसे प्यार किया था मैंने,
तेरी अगर मगर ने रोका।

- गोविन्द गुँजन।

राहुल की मांग, जम्मू-कश्मीर को जल्द मिले राज्य का दर्जा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा कि, संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए। राहुल ने अपने लेटर में प्रधानमंत्री मोदी के पुराने

● पीएम मोदी को लिखा लेटर, कहा- मानसून सत्र में बिल लाया जाए

दो बयानों का भी जिक्र किया। जब पीएम ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। इसके अलावा राहुल ने सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का भी अनुरोध किया। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुर्नगठित किया गया था।

म.प्र. में हर सेक्टर में हैं बड़ी संभावनाएं

स्पेन के निवेशकों को देंगे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताओं के संवाहक हैं। दोनों देशों ने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पुरा संस्कृति को आगे बढ़ाया है। दोनों देश जुड़वा भाईयों की तरह हैं। अब विकास के मामले में भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। संस्कृति के साथ-साथ तकनीक में भी स्पेन की एक अलग ही पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकासशील प्रदेश है। यहां निवेश करना निःसंदेह फायदे का सौदा है। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश की बेजोड़ खूबियां बताते हुए कहा कि यदि आप भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बार मध्यप्रदेश अवश्य आइये, मध्यप्रदेश को भूल नहीं पाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज, पर्यटन, बड़े उद्योग, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, तकनीकी विकास से जुड़े उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में एमपी टूरिज्म सबसे तेजी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भरपूर भू-संपदा उपलब्ध है, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करने से विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश, भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम लॉजिस्टिक सेक्टर में अग्रणी बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत के किसी और राज्य में भी उद्योग स्थापित करते हैं, तब भी आपको मध्यप्रदेश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी।

अपार संभावनाओं का भरोसेमंद स्थल मप्र : प्रमुख सचिव

औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि म.प्र. अपार संभावनाओं का भरोसेमंद निवेश स्थल है। प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन और स्थिर नेतृत्व इसे उद्योगों के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य बनाते हैं। स्पेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध लगातार सुदृढ़ हो रहे हैं। वर्ष 2024 में भारत से स्पेन को 5.93 बिलियन यूरो का निर्यात हुआ, जिसमें मध्यप्रदेश का योगदान 58.5 मिलियन यूरो का रहा। यह हमारी निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार की मांग के प्रति तत्परता को दर्शाता है। विशेष रूप से ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और वस्त्र जैसे क्षेत्र इसमें अग्रणी हैं।

मिल गया 114 साल के फौजा सिंह का कातिल

● फॉर्च्यूनर भी जब्त, घर के बाहर मारी थी टक्कर

चंडीगढ़ (एजेंसी)। दुनिया भर में टर्बनड टॉर्नेडो के नाम से मशहूर एथलीट फौजा सिंह को गाड़ी से टक्कर मारने वाले को जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लो के रूप में हुई है जो करतारपुर के दासूपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पीबी 20 सी 7100 को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ में अमृतपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फौजा सिंह की सैर करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें वह गांव से अकेले ही नेशनल हाईवे की ओर सैर करने के लिए जाते दिख रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टक्कर मारने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक उन्हें टक्कर मार कर फरार हो जाता है।

विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता

हमें बना रही कमजोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा विदेश से इम्पोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी सीएएएस (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एएवी (अनमैंड एरियल व्हीकल) और काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम की प्रदर्शनी में कहीं। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा- मुझे लगता है कि ड्रोन्स इवॉल्यूशनरी (विकासवादी) हैं और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है। जैसे-जैसे उनकी तैनाती और दायरा

● सीडीएस ने कहा- स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी ● कहा- कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते

बाणसागर के 8,सतपुड़ा डैम के 5 गेट खुले

● आलीराजपुर में 5 घंटे की बारिश में उर नदी उफनी ● डिंडौरी में नर्मदा में मंदिर डूबे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। आज 18 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट है। आलीराजपुर में सुबह 6 बजे से हो रही लगातार बारिश से उर नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पुलिया से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। पानी घरों में घुस गया है।

शहडोल के बाणसागर डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं, बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा बांध के 5 गेट 2 फीट तक खोले गए हैं। इन गेटों को बुधवार सुबह 10:45 बजे खोलकर 8390 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिंडौरी और मंडला में भी तेज बारिश जारी है। यहां नर्मदा नदी में पानी बढ़ रहा है। कई जगहों पर पुल डूब गए हैं। मंडला के सुभाष वार्ड में पानी निकासी नहीं होने के चलते सड़क पर तीन फीट के ऊपर पानी भर गया है। डिंडौरी में नर्मदा घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं।

25 से ज्यादा जिलों में हुई बारिश- मंगलवार को ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा ग्वालियर में 2.3 इंच पानी गिर गया। खरगोन में डेढ़ इंच, सीधी में 1 इंच और उमरिया में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा। शाजापुर और रायसेन में भी तेज बारिश का दौर चला। भोपाल, दतिया, इंदौर, नर्मदापुरम, श्योपुर, शिवपुरी, मंडला, सागर, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, आगर-मालवा, देवास समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि, बीते 24 घंटे में बारिश या वर्षाजनित हादसों में किसी मौत की खबर नहीं है।

इस मानसूनी सीजन में मध्यप्रदेश में औसत 18.2 इंच बारिश हो गई है, जो कोटे से आधी है। अब तक की औसत बारिश से यह 72 प्रतिशत यानी 5.6 इंच ज्यादा है।

"डैम लबालब

शहडोल में मानसून की बारिश के चलते बाणसागर डैम में पानी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने डैम के स्पिल वे के आठ गेट को 2 मीटर की ऊंचाई तक चौथी बार खोलने का फैसला लिया है। वर्तमान में डैम का जलस्तर 339.96 मीटर तक पहुंच गया है, जो पूर्ण जल भराव स्तर (F.R.L.) 341.64 मीटर से केवल 1.68 मीटर कम है। स्पिल वे के जरिए 3080.00 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परियोजना के कार्यपालन यंत्री विनोद ओझा ने बताया कि चार बार गेट खोलने का फैसला लिया गया है, और गेट भी खोले जा सकते हैं। हम निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

शिवपुरी लिंक रोड पर निर्माणाधीन मकान गिरा, मजदूर की मौत- ग्वालियर में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (शिवपुरी लिंक रोड) स्थित आशाराम आश्रम के पास एक निर्माणाधीन मकान गिर गया। जिसमें दीवार के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबा हटाते हुए शव को अस्पताल भिजवाया। हादसा 12.30

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 17 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहें, ऑयल बोर्ड डिस्प्ले लगाएं

● बच्चों का मोटापा कम करने सीबीएसई का स्कूलों को निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या को देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा कदम उठाया है। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह बच्चों के मोटापे पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें ऑयल बोर्ड बनाकर जागरुक करें। इसके अलावा बच्चों को शारीरिक गतिविधि जैसे सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल, आंकड़े बताते हैं कि वयस्कों और बच्चों दोनों में मोटापे में तेजी

से बढ़ोतरी हो रही है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पांच में से एक से ज्यादा वयस्क अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है। 2025 में प्रकाशित द लैंसेट जीबीडी 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन के अनुसार भारत में अधिक वजन और मोटे वयस्कों की संख्या 2021 में 18 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 44.9 करोड़ हो जाने का अनुमान है।

विधानसभा में लुंगी-बनियान पहनकर पहुंचे विपक्षी विधायक

● शिवसेना एमएलए के खिलाफ किया प्रदर्शन

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बुधवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने 'लुंगी-बनियान' पहनकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायक हॉस्टल की कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट के खिलाफ

किया गया। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधान परिषद में नेता अंबादास दानवे, एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक जीतेन्द्र आव्हाड समेत कई विपक्षी नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने अपने पारंपरिक कपड़ों के ऊपर बनियान और तौलिया (लुंगी की तरह) पहनकर 'गुंडा राज' के खिलाफ नारेबाजी की। अंबादास दानवे ने कहा कि जब विधायक कैंटीन में ही मारपीट कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विधायक की आलोचना कर चुके हैं। शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने मारपीट की थी।

अकबर 'क्रूर लेकिन सहिष्णु', औरंगजेब 'कट्टर धार्मिक'

● एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा ● कक्षा 8 के सिलेबस में हुआ शामिल, कवर में दी तस्वीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अकबर का शासन 'क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर-इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर-मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। किताब में मुगल सल्तनत के पहले शासक बाबर को तुर्क-मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। इसके साथ बताया गया कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को

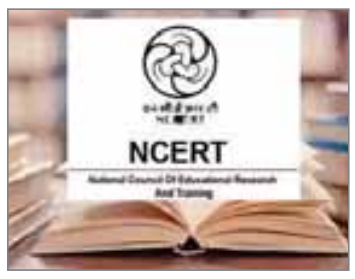

हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। बाबर का बेटा हुमायूं साम्राज्य को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और एक समय के लिए उसने शेर शाह सूरी से हारकर साम्राज्य खो भी दिया था। किताब में बताया गया है कि कैसे शेर शाह सूरी के हिंदू सेनापति हेमू को अकबर की सेना ने पकड़ा और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद सिर कलम कर दिया। अकबर के शासन को किताब में क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी अकबर के विजय पत्र से मिली-इसके अलावा अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, राजपूतों का स्वागत किया।

एनसीईआरटी ने कहा-

इतिहास की जड़ों को जानना जरूरी- किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का भी जिक्र है। इस बारे में एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा, इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज किसी को उनके लिए दोषी ठहराना गलत होगा। सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत को समझना ही ऐसा भविष्य बनाने का सही तरीका है जहां ये घटनाएं दोबारा न हों। इसी साल एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में भी बदलाव किया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी की टेक्स्टबुक्स से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जोड़ा गया है।

उत्तराखंड के स्कूलों में रोज पढ़े जाएंगे गीता के श्लोक

● प्रार्थना सभा में अर्थ के साथ होगा गीतापाठ, 17 हजार स्कूलों पर फैसला लागू

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड राज्य के सभी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के बाद मंगलवार से ही नियम प्रदेश भर के लगभग 17 हजार सरकारी स्कूलों पर लागू हो गया है। शिक्षा निदेशक डॉ सती ने बताया कि हर दिन स्कूल में गीता के श्लोकों का केवल उच्चारण नहीं होगा, बल्कि उनका अर्थ भी समझाया जाएगा। इसका मकसद स्कूली बच्चों को प्राचीन भारतीय परंपराओं से अवगत कराना है। इससे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलेपमेंट होने के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। जारी आदेश में लिखा गया है कि हर दिन एक मूल्य आधारित श्लोक प्रार्थना सभा में बोला जाएगा और सूचना पट पर अर्थ सहित लिखा भी जाएगा। टीचर्स भी समय-समय पर श्लोकों की व्याख्या करते हुए बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी देंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में प्राचीन विषयों को शामिल करने का निर्देश है। इसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम केंद्र द्वारा तय किया जाएगा, वहीं 30 फीसदी राज्य तय करेगा। इसी नीति के तहत उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

जेवलिन मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा भारत!

● अमरीका को लिखी चिट्ठी, प्रोडक्शन में चाहिए साथ ● विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने का है प्लान

वॉशिंगटन (एजेंसी)। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन का इस्तेमाल करते हुए रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अब भारत उसी मिसाइल को अमेरिका के साथ मिलकर बनाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका को जवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए औपचारिक रूप से एक 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' भेज दिया है। दोनों देशों के बीच जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर लंबे वक्त से बात चल रही थी और अब भारत ने आधिकारिक तौर पर चिट्ठी भेज दी है। भारत, मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का निर्माण करना चाहता है, जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर आसानी से फायर कर सकता है। इसीलिए इस मिसाइल को टैंकों का काल माना जाता है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें अमेरिका की सबसे एडवांस थर्ड जेनरेशन की एंटी-टैंक मिसाइलें मानी जाती हैं। रूस ने जब अपने सैकड़ों टैंकों को यूक्रेन में भेज दिया था, उसके बाद यूक्रेन को अमेरिका ने इस मिसाइलों को सौंपा था। यूक्रेन के जवान कहीं से भी छिपकर रूसी टैंकों को निशाना बना रहे थे। आखिरकार रूस को अपनी अग्रिम पंक्ति से अपने टैंकों को हटाना पड़ा। यह सिस्टम टॉप-अटैक क्षमता के लिए जाना जाता है,

यानी यह दुश्मन के टैंक को ऊपर से निशाना बनाकर नष्ट करता है। टैंक का ये हिस्सा सबसे कमजोर होता है, इसीलिए टैंक काफी आसानी से ध्वस्त हो जाता है। जमीनी लड़ाई के समय ये मिसाइल काफी ज्यादा असरदार साबित हुआ है। दि हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक सीनियर डिफेंस अधिकारी ने अमेरिका को चिट्ठी भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को लेटर सौंप दिया गया है। भारतीय अधिकारी ने कहा कि सौदा हो जाने पर ये भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करेगा और भारत अपनी जरूरत के मुताबिक एंटी टैंक का खुद प्रोडक्शन कर पाएगा। उन्होंने कहा है कि बातचीत अंतिम चरण में है। अधिकारी ने ये भी कहा है कि वे आपातकालीन खरीद के तहत जेवलिन मिसाइलों की खरीद के लिए पहले से ही अमेरिका के संपर्क में हैं। दरअसल, भारत की सेना पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के लिए ऐसे मिसाइल सिस्टम चाहती है, जो काफी हल्के हों और जवान आसानी से उसे ऑपरेट कर सकें।

पटना में रनवे टच करके फिर दोबारा उड़ा विमान

● 4 चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग हो पाई ● 173 यात्रियों की अटकी रहीं सांसें, मिली राहत

पटना (एजेंसी)। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। फिर, तीन-चार चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया। इस दौरान दिल्ली से पटना आ रहे करीब 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रहीं। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत महसूस की। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार की रात करीब 9 बजे दिल्ली से पटना आने के बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। हालांकि, विमान टचिंग पॉइंट को थोड़ा ओवरशूट कर गया था। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। पायलट को लगा कि रनवे पर विमान को नहीं रोक पाएंगे तो उन्होंने दोबारा विमान को ऊपर उठा लिया। ऐसा होता देख यात्री परेशान हो गए। यात्रियों को लगा कि कोई विमान रनवे पर होगा।

बंगालियों से भेदभाव पर सीएम ममता का पैदल मार्च

● कहा-बीजेपी बंगाली बोलने वालों को परेशान कर रही

सुवेंदु बोले-ये अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।

ममता ने कहा कि बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक

निकाली गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। कोलकाता के अलावा पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। सीएम ममता ने कहा,मैं आपको (बीजेपी) चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोलने वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। मैं बंगालियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी और विदेशी कहकर प्रताड़ित और जेल और डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है।

छांगुर बाबा की मदद कर रहे थे एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर!

● यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा, धर्मांतरण का है मामला

लखनऊ (एजेंसी)। धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर जांच एजेंसियों की परत-दर-परत पड़ताल में लगातार बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब कुछ अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की गोपनीय जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर के मददगार रहे चार प्रशासनिक अफसरों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी अफसर साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे हैं। एक रिपोर्ट में मुताबिक, एक एडीएम, दो सर्किल ऑफिसर (सीओ) और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इन अफसरों पर छांगुर बाबा के इशारों पर काम करने का आरोप है और ये कई मौकों पर उसे संरक्षण भी देते थे। एटीएस की रिमांड के दौरान इन अफसरों के नाम उछले हैं।

ट्रंप के बाद अब नाटो ने दी भारत को धमकी

● कहा-रूस को नहीं समझाया तो लगाएंगे 100 फीसदी टैरिफ

कहा-रूस को जंग रोकने को कहें, वरना नतीजा भुगतना होगा

ब्रसेल्स (एजेंसी)। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है।

रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए, ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से लें। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है।

बिहार वोटर लिस्ट को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष

संसद का मानसून सत्र

सदन में सरकार को घेरने की तैयारी, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन- एसआईआर) को लेकर विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुट गया है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और कांग्रेस की अगुआई में चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयार कर रही हैं। यह एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग सदन में किसी अहम मामले पर तत्काल चर्चा करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए किया जाता है। सरकार की सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशों के बावजूद बिहार की चुनावी सियासत बड़ी बाधा बन सकती है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सरकार मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की ढाल लेकर सदन में पहुंचेगी। 47 दिन पहले हुई थी मानसून सत्र की घोषणा संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसकी घोषणा 47 दिन पहले ही कर दी गई थी। आमतौर पर सत्र शुरू होने की जानकारी एक हफ्ता या 10 दिन पहले दी जाती है। इतने समय पहले सत्र की घोषणा करने का कारण यह था कि विपक्ष उस समय 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था। मानसून सत्र की तारीख सामने आने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि सरकार ने विशेष सत्र की मांग से ध्यान भटकाने के लिए अचानक मानसून सत्र की घोषणा की है। भारत के इतिहास में कभी भी 47 दिन पहले सत्र की घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री विशेष सत्र से तो भाग सकते हैं, लेकिन मानसून सत्र से नहीं।

रील बनाने के बाद सोई, फिर उठी ही नहीं

इंदौर। हार्ट अटैक के चलते युवाओं की मौत के मामले बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। इस बीच इंदौर का एक केस चौकाने वाला है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी का भट्टा निवासी 16 वर्षीय लावण्या जैन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिवार को आशंका है कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हुई है। परिजन ने बताया कि रविवार दोपहर में वह रील बनाने के बाद सो गई थी। इसके बाद उसे उठाया, लेकिन वह उठी नहीं। पास के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक ने अभी 12 वीं की परीक्षा पास की थी। उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

हाईस्कूल के छात्र ने फांसी लगाई

इंदौर। अज्ञात कारणों के चलते हीरानगर में रहने वाले 16 वर्षीय सुशील चौहान ने गौरी नगर स्थित अपने घर में सोमवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुशील कक्षा 10वीं का छात्र था और घटना के समय वह घर में अकेला था। सुशील की मां की मौत 6 माह पहले और पिता की 20 दिन पहले हुई है। उसका बड़ा भाई शुभम निजी कॉलेज में जॉब करता है। वह चाचा के परिवार और भाई के साथ रहता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। इसी प्रकार, बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक का नाम राजेंद्र पिता नर्मदा प्रसाद (70) निवासी गाड़ी अड्डा बताया जा रहा है। जीआरपी ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय भेजा है। वहीं मामले में आगे जांच की जा रही हैं। उधर बाणगंगा थाना इलाके के नरवल कांकड़ निवासी बसंत पिता नब्बू (36) ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

युवक से साढ़े 10 किलो गांजा जब्त

इंदौर। रीजनल पार्क के समीप से तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से गांजा जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच टीम द्वारा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के पास रीजनल पार्क आरोपी सोहन डावर निवासी ग्राम शैल महेश्वर खरगोन को पकड़ा। आरोपी से 10 किलो 504 ग्राम गांजा जब्त किया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया जल्द रुपए कमाने की नीयत से मादक पदार्थ सस्ते में खरीदी कर महंगे दामों पर नशे के आदी लोगों को बिक्री करने का कार्य करता था।

आरक्षित विद्यार्थियों को परीक्षाओं की कोचिंग

इंदौर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को नीट, जेईई, क्लैट, एनडीए, टॉफल और एसएटी जैसी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। सहायक संचालक अनिल सोनी ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं या अध्ययनरत हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक न हो और जो किसी अन्य कोचिंग योजना से लाभ न ले रहे हों। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 80474-95118 पर संपर्क किया जा सकता है। छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है ताकि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें।

अब थानों में लगने लगी गुंडों की पाठशाला

इंदौर। लगातार आपराधिक वारदातों में लिप्त बदमाशों को पुलिस थाने में कड़ा सबक सीखाती है। जिलाबदर करने, रासुका में गिरफ्तार कर जेल भेजने, बांड ओवर करने के बाद अब उनकी पाठशालाएं लगाने की सिलसिला शुरू हो गया है। इस पाठशाला में थाना स्तर पर गुंडे बदमाशों की पकड़कर उनके हाथों में पेन, कागज थमा दिया जाता है। कागज पर गुंडों ने टूटी फूटी हिंदी भाषा में अपराध नहीं करने की शपथ ली। यही नहीं, अपराध करने के बाद जीवन में आई परेशानियों को भी साझा किया। बदमाशों ने कागज पर लिखा कि वे अपने बच्चों को इस दुनिया से दूर रखेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। वे जो कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे।

साइबर फ्रॉड की जानकारी से जाना बचने का मंत्र

इंदौर। शहर में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने पुलिस लगातार काम कर रही है। क्राइम ब्रांच भी जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम दृष्टि कोचिंग इंस्टिट्यूट पहुंची। यहां छात्रों की कार्यशाला लगाकर उन्हें साइबर फ्रॉड की जानकारी देते हुए बचने के मंत्र बताए। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त क्राइम राजेश दंडोतिया ने टीम के साथ 350 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों की जानकारी दी और साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन-1930, पोर्टल साइबर क्राइम इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 7049124445 आदि पर किस प्रकार शिकायत करें। पुलिस इन पर किस प्रकार कार्रवाई करती है आदि के संबंध में समझाया। उन्होंने कहा कि हम लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा काम डिजिटल रूप में ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें जरा सी गलती होने पर साइबर फ्रॉड होने की संभावना रहती है। इस दौरान पुलिस टीम ने वहां सभी को साइबर अवेयरनेस के पम्पलेट्स व स्टिकर्स भी दिए और सभी को साइबर जागरूकता लाने में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया।

तहसीलदारों मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा

भोपाल/इंदौर। राज्य के राजस्व , तहसीलदारों नायब तहसीलदारों ने न्यायालयीन व गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन योजना को लागू करने के लिए भोपाल में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन और प्रमुख सचिव राजस्व को ज्ञापन सौंपा । जिला स्तर पर भी विभिन्न जिलों में विभिन्न जिलों में तहसीलदारों ने कलेक्टर और एसडीएम को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौपा ।तहसीलदारों का दावा है कि न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कर्तव्य विभाजन बिना किसी अध्ययन और समिति की सिफारिश के बिना कर दिया गया है जिससे कर्तव्य विभाजन की मूल भावना ही समाप्त हो गई है।

प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी अपनाएगा इंदौर का सफाई मॉडल

वाराणसी निगम को इंदौर के अफसरों ने स्वच्छता मॉडल समझाया

इंदौर। देशभर में स्वच्छता में सात बार अव्वल रहने वाला इंदौर अब अपने सफाई मॉडल को अन्य शहरों में भी साझा करने जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब इंदौर के नगर निगम और प्रशासनिक अफसर किसी दूसरे शहर में जाकर सफाई को लेकर मार्गदर्शन देंगे। यह शहर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। आज मंगलवार को वाराणसी नगर निगम के सभी बड़े अफसरों की टीम को इंदौर की टीम ने यहां की सफाई व्यवस्था को विस्तार से समझाया। इंदौर की साफ-सफाई के मॉडल का अध्ययन करने अभी तक देश और दुनिया के 100 से ज्यादा शहरों के अफसर इंदौर आ चुके है। यह पहली बार है, कि इंदौर के अफसर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम के अफसरों के साथ उन्हें सफाई की टिप्स दे रहे हैं। इंदौर मॉडल को

वाराणसी में लागू कराने के लिए इंदौर और भोपाल से अफसरों की टीम रवाना हुई। मध्य प्रदेश के ये अफसर चार दिन वाराणसी में ही रुकेंगे और वहां के संसाधनों के हिसाब से सफाई व्यवस्था को लेकर टिप्स देंगे। दिल्ली से नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए गए थे कि वाराणसी में इंदौर जैसी सफाई व्यवस्था लागू की जाए। इसके बाद इंदौर और भोपाल के विशेषज्ञों की टीम ने वाराणसी के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें वीडियो, फोटो और दस्तावेज शामिल थे। अब अफसर वाराणसी में चार दिन रुक कर वहां के संसाधनों के अनुसार सफाई मॉडल को समझाएंगे। मंगलवार को इंदौर और वाराणसी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई जिसमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, गीला-सूखा कचरे की छंटाई, कचरे का रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

दोनों शहरों के अफसरों की बैठक

वाराणसी नगर निगम की टीम के साथ आज इंदौर के अफसरों की स्वच्छता पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में घर-घर कचरा संग्रहण, गीला-सूखा कचरा सेग्रीगेशन, कचरे के रिसाइकल सहित अन्य विषयों पर जानकारी साझा की गई। इस बैठक में विवेक अग्रवाल, संकेत भोंडवे, आशीष सिंह, शिवम वर्मा, अभिलाष मिश्रा एवं वाराणसी के संभाग आयुक्त एस राजलिंगम, वाराणसी नगर निगम के आयुक्त अक्षत वर्मा और निगम की स्वच्छता टीम उपस्थित रही।

इंदौर के सफाई मॉडल की खासियत

- इंदौर में कचरा डोर टू डोर तरीके से संग्रहित होकर सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड जाता है।
- छह अलग-अलग प्रकार के कचरे वाहनों के माध्यम से ही अलग हो जाते है। प्लांट पर कचरा अलग नहीं किया जाता।
- शहर में एक भी कचरा पेटी नहीं है। लोग खुले में कचरा नहीं फेंकते है।
- नगर निगम एप (311) के माध्यम से भी कचरा वाहनों को बुलवाने की सुविधा रहवासियों को मिल रही है।
- इंदौर में कचरे से खाद और सीएनजी बनाई जा रही है। प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाया जा रहा है, जो सीमेंट फैक्ट्रियों में काम आता है। इसके अलावा मलबे से पेवर ब्लॉक बनाए जाते है।
- इंदौर के स्वच्छता मॉडल की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बन रही है।

आरटीओ की सख्ती, 50.73 लाख का टैक्स, 3.60 लाख की पेनल्टी वसूली

स्कूली वाहनों, लोक परिवहन वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों की जांच

इंदौर। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के पालन में इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने बकाया मोटरयान कर एवं पेनल्टी की वसूली के लिए व्यापक और सघन अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के अंतर्गत गत 7 दिनों में कुल 50 लाख 73 हजार 152 रुपये का बकाया मोटरयान कर एवं 3 लाख 60 हजार रुपये की पेनल्टी वसूली की गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बकाया कर नहीं चुकाने वाले वाहन स्वामियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया। जिन वाहन स्वामियों से संपर्क नहीं हो पाया, उनके निवास स्थान पर नोटिस पहुंचाया गया। साथ ही जिन वाहन मालिकों ने कर जमा करने से इंकार किया, उनके विरुद्ध वाहन जब्त की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान कुल 81 वाहनों से लंबित कर की वसूली की गई। परिवहन विभाग द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि जिन वाहन स्वामियों पर मोटरयान कर बकाया है, वे शीघ्र ही कर जमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए जाएंगे।

उड़नदस्ता की कार्रवाई भी जारी- इंदौर आरटीओ के परिवहन उड़नदस्ता द्वारा स्कूली वाहनों, लोक परिवहन वाहनों तथा अन्य वाणिज्यिक वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। गत सप्ताह में 95 से अधिक वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत 3 लाख 60 हजार रुपए की पेनल्टी भी वसूली गई। जांच के दौरान विशेष रूप से ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, स्पीड गवर्नर की अनुपस्थिति, तथा अधूरे दस्तावेज जैसे मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्कूल व कॉलेज वाहनों की भी गहन जांच की गई, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भाइयों में नहाने को लेकर विवाद 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या की

ट्यूशन जाने की जल्दी थी, छोटे ने नहाने नहीं दिया तो फांसी लगाई

इंदौर। शहर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। नहाने की बारी को लेकर दो सगे भाइयों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया। 12 साल के आतिफ ने गुस्से में आकर बाथरूम से लगे कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आतिफ का अपने छोटे भाई से सुबह नहाने की बारी को लेकर विवाद हुआ। छोटा भाई पहले नहाने की जिद पर अड़ा था, जबकि आतिफ बार-बार कह रहा था कि उसे ट्यूशन जाना है, इसलिए वह पहले नहाना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। परिजनों के अनुसार, आतिफ थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। विवाद के बाद वह चुपचाप बाथरूम से लगे कमरे में गया और वहां फांसी लगाकर जान दे दी। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आया, तो परिजनों ने जाकर देखा और घटना का खुलासा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्ट्म के लिए भेजा गया। जांच अधिकारी रघुवीर जाट ने बताया कि प्रथम दृष्टया नहाने की बात को लेकर विवाद के बाद आत्महत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के फूफा मोहम्मद सलीम ने भी पारिवारिक विवाद की पुष्टि की है।

'वाटर एटीएम' की योजना हवा हवाई घोषणा के बाद पूरी गर्मी निकल गई

शहर में लगने वाले 25 वाटर एटीएम के स्थान भी तय हो गए

इंदौर। इस बार गर्मी के मौसम से पहले मार्च में नगर निगम ने मेयर इन कांउसिल की बैठक में 'वाटर एटीएम' नाम का नया शिगूफा छोड़ा था। दावा किया गया था कि अब शहर में लोगों को भरी गर्मी में गला तर करने के लिए पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम ने न्यूनतम भुगतान पर पीने का साफ व ठंडा पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। नगर निगम ने शहर के 25 स्थानों पर वाटर एटीएम लगाने का फैसला किया था। कहा गया था कि बैंक के एटीएम की तरह भुगतान करने पर निर्धारित मात्रा में स्वच्छ व ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। पर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी कई घोषणाओं की तरह ये घोषणा भी हवा में उड़ गई। नगर निगम की योजनाएं की कई घोषणाएं हवा में गायब हो गई। उन्हीं में से एक वाटर एटीएम को भी पंख लग गए। जिम्मेदारों ने बजट सेशन के दौरान खूब घोषणाएं कीं। आनन-फानन में शहर में लगने वाले 25 वाटर एटीएम के स्थान तय कर टेंडर भी पास कर दिए गए। लेकिन, जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिन अधिकारियों पर इस योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी है, उन्हें ही नहीं पता कि इन वाटर एटीएम को लगाना कहां है, कैसे लगाना है और किस जरूरत के हिसाब से लगाना है। नतीजा ये कि अधिकारी खुद चक्करघिन्नी बन गए। बैठकों पर बैठक हो रही हैं, फाइलें घूम रही हैं, लेकिन न कोई दिशा है, न कोई ठोस कार्ययोजना। शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सोच तो सराहनीय थी, पर बिना तैयारी के उठाया गया यह कदम अब मज़ाक बनता दिख रहा है। न तो जनसुनवाई में इस पर कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है और न जमीनी अमले को किसी तरह की स्पष्ट जानकारी है। सवाल उठता है कि जब अधिकारियों को ही नहीं पता कि करना क्या है, तो टेंडर की यह जल्दी किस बात की थी? कहीं यह योजना भी बाकी घोषणाओं की तरह सिर्फ कागजों में सिमट कर न रह जाए।

इंदौर मेट्रो का एयरपोर्ट परिसर में भूमिगत स्टेशन का निर्माण शुरू

जनवरी तक गांधी नगर से रेडिसन स्क्वायर तक मेट्रो शुरू

इंदौर। मेट्रो के पहले भूमिगत स्टेशन का काम शुरू हो गया। यह एयरपोर्ट परिसर क्षेत्र में चल रहा है। मेट्रो प्रबंधन का यह निर्माण कार्य गांधी नगर स्टेशन और देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। तैयारी के तौर पर एयरपोर्ट के पास खुदाई का काम शुरू हो गया। प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ड्रोन सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। इंदौर में पहला भूमिगत मेट्रो स्टेशन हवाई अड्डे के परिसर में बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट से यात्रियों को मेट्रो की सीधी पहुँच मिल सकेगी। भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए बड़े पैमाने पर उत्खनन मशीनें मौके पर पहुँच चुकी हैं और खुदाई का काम भी शुरू हो गया। मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट से बिजासन टेकरी तक लंबा होगा, जो इंदौर मेट्रो की पहला एकीकृत भूमिगत-एलिवेटेड मेट्रो सिस्टम होगा। मेट्रो लाइन एयरपोर्ट के पास भूमिगत खंड से धीरे-धीरे ऊपर उठेगी। एयरपोर्ट रोड पर अलग-अलग ऊँचाई पर खंभे पहले ही बनाए जा चुके हैं और स्टेशन का डिज़ाइन दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की तरह बनाया जा रहा है। एस्कलेटर से हवाई अड्डे के टर्मिनल को सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा, ताकि पैदल दूरी कम हो, खासकर सामान लेकर आने वाले यात्रियों के लिए यह आसान होगा। मेट्रो की योजना के तहत, जनवरी 2026 तक गांधी नगर से रेडिसन स्क्वायर तक मेट्रो की सेवा शुरू होने की उम्मीद है। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर व्यावसायिक परिचालन शुरू करने के बाद, मेट्रो कॉर्पोरेशन ने सुपर कॉरिडोर स्टेशन संख्या 3 से रोबोट स्क्वायर तक 11 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम की गति बढ़ा दी है। गांधी नगर और रोबोट स्क्वायर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन, यात्रियों की घटी संख्या एक बड़ी समस्या है। यात्रियों की पूरी क्षमता का एहसास तभी होगा, जब एयरपोर्ट से रेडिसन स्क्वायर के बीच संपर्क स्थापित हो जाएगा। एयरपोर्ट से संपर्क फिलहाल मेट्रो परियोजना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सोनम के भाई ने राजा के परिवार को आसानी से नहीं दिए 10 लाख के गहने

गोविंद ने बहानेबाजी की, राजा के परिवार ने पुलिस से की शिकायत

इंदौर। शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को 10 लाख रुपये के गहने वापस लौटा दिए हैं। इसमें जो कहानी सामने आई वो काफी चौकाने वाली है। दरअसल राजा के परिवार ने गोविंद से उन गहनों को वापस लौटाने के लिए कहा था जो उन्होंने शादी के दौरान सोनम रघुवंशी को गिफ्ट किए थे। जानकारी के मुताबिक गोविंद राजा के परिवार को गहने लौटने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इस मामले में जब भी बात होती तो वह कभी खुद के पास अलमारी की चाबी ना होने की बात कहता, तो कभी माता-पिता से पूछकर गहने लौटाने की बात कहता। पिछले

दिनों तो गोविंद ने राजा के भाई विपिन का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद विपिन रघुवंशी ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत करते हुए बताया कि सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद उनका फोन नहीं उठा रहा है। उससे गहने वापस देने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक उसने इन्हें नहीं लौटाया है। विपिन ने पुलिस द्वारा गोविंद को फोन लगाया था। इसके बाद गोविंद सोनम रघुवंशी को राजा के परिवार द्वारा गिफ्ट किए गए गहने लेकर राजेंद्र नगर थाने पहुंचा। गहनों में अंगूठी, बिछड़ी, पायल, चूडियां, टीका, रानी हार और सोने का हार शामिल था। वहीं कुछ गहने मंगलसूत्र, अंगूठी, बिछड़ी और पायल शिलांग पुलिस के पास जब्त हैं।

सोनम परिवार से कोई रिश्ता नहीं- राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अब उनका सोनम रघुवंशी से कोई रिश्ता नहीं है। उसने हमारे भाई की हत्या करवा दी। परिवार ने बहू मानकर उसे लाखों रुपये के सोने और चांदी के गहने दिलवाए थे। इन्हीं गहनों को वापस लौटाने के लिए गोविंद से कहा गया था। पर गोविंद ने जब फोन उठाना बंद कर दिया तो पुलिस की मदद ली गई।

संपादकीय

अंतरिक्षवीर शुभांशु !

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से अपने चार तीन और साथियों के साथ स्पेस में जाना और वहां कई वैज्ञानिक प्रयोग कर सकुशल वापस लौटना अपने आप बड़ी और देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अब देश के दूसरे अंतरिक्ष कुमार हैं। शुभांशु की यह अंतरिक्ष यात्रा और उससे मिले विरल अनुभव भारत के भावी गगनयान अभियान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुभव का भरपूर लाभ इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। क्योंकि इस एक्सिओम-4 मिशन ने भारत के अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को वास्तविक अंतरिक्ष स्थितियों में परखा है। शुभांशु ने अंतरिक्ष में 18 दिन बिताए। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन और तैयारी करा रहे इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन के पूर्व कमांडेंट, एयर वाइस मार्शल अनुपम अग्रवाल ने कहा कि एक्सिओम-4 मिशन ने वास्तविक अंतरिक्ष परिस्थितियों में भारत के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण प्रोटोकॉल का परीक्षण और सत्यापन किया है। इस मिशन के लिए न केवल शुभांशु शुक्ला का सेलेक्शन सही था, बल्कि हमने जो टेस्ट स्टैंडर्ड विकसित किए, जो प्रक्रियाएं अपनाई और साइक्लोजिकल सेलेक्शन में पद्धतियां अपनाई, उन सबका अब वास्तविक माइक्रो ग्रेविटी परीक्षण किया जा रहा है। हम उनका गहन अध्ययन करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बेसलाइन डेटा एकत्र करने और उसकी व्याख्या करने के हमारे तरीके सही थे या नहीं। ध्यान रहे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन ड्रैगन जरूर ग्रेस अंतरिक्ष यान के कैलिफोर्निया तट पर उतरने के साथ समाप्त हो गया है लेकिन गगनयान का सफर अभी बाकी है। भारत का नया सितारा बन चुके शुभांशु स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए पहला अनुभव जुटाकर लाए हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान के लिए चयनित 39 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला टीम के सबसे युवा सदस्य थे। भारतीय वायु सेना के अधिकारी और टेस्ट पायलट शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा की 1984 की ऐतिहासिक उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारत ने इस मिशन के लिए 550 करोड़ रू. में एक सीट बुक की थी। शुभांशु को पिछले वर्ष भारत के गगनयान कार्यक्रम में चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया। उन्होंने रूस के गगारिन कास्मोनाट ट्रेनिंग सेंटर और इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन गगनयान के 2027 में निर्धारित लांच से पहले शुक्ला को एएक्स-4 क्रू का हिस्सा बनने का अवसर मिल गया। गौरतलब है कि कई बार स्थगन के बाद एक्सिओम-4 मिशन के पायलट शुक्ला ने 25 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट पर उड़ान भरी थी। 18 दिनों के अपने अंतरिक्ष प्रवास में उन्होंने आईएसएस पर रहते हुए सात प्रयोग किए जो आगे चलकर मिशन गगनयान का हिस्सा होंगे। उन्होंने जीव विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी और संज्ञानात्मक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में माइक्रोग्रैविटी प्रयोग किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए समय के दौरान प्राप्त अनुभव अगले दो वर्षों में नियोजित गगनयान मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसरो ने यह मिशन इसलिए शुरू किया ताकि वह अनुभव प्राप्त कर सके जो गगनयान मिशन में हमारी मदद करेगा। गगनयान मिशन इस साल के अंत में एक मानवरहित उड़ान के साथ शुरू होगा। जिसके बाद दो और मानवरहित उड़ानें होंगी। इसके बाद एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वह दो से सात दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। कुल मिलाकर यह सफल और उम्मीदें जगाने वाला मिशन रहा।

देश में पुल हादसों का सच, खोखली निगरानी

नजरिया

शाहिद नकवी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक निर्माणाधीन पुल इस लिए चर्चित हो गया कि उसमें एक जगह 90 डिग्री का मोड़ आ गया। कुछ निलम्बन के बाद मामला फिलहाल ठंडा है। एक और उदाहरण देखिए, 2022 में गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल ढह गया, जिसमें विशेषज्ञों ने डिज़ाइन और मरम्मत में खामियों को जिम्मेदार ठहराया। एक शैक्षिक अध्ययन 2019 के अनुसार, डिज़ाइन की कमियाँ 20-25 प्रतिशत पुल हादसों में योगदान देती हैं। निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग, जैसे कमजोर सीमेंट, सरिया या अन्य सामग्री, पुलों की संरचनात्मक अखंडता को प्रभावित करता है। पुलों के निर्माण में गलत डिजाइन की बात तो होती है लेकिन गुणवत्ता पर चर्चा कम ही होती है। जबकि एक तकनीकी जानकार का कहना है कि पुल पर सड़क हादसे डिजाइन में तकनीकी गड़बड़ी से तो हो सकते हैं, लेकिन उसके ढहने के पीछे अधिकांश मामलों में निम्न गुणवत्ता ही होती है।

भारत में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बार-बार होने वाली पुल ढहने की घटनाएं इस प्रगति पर सवाल उठाती हैं।ये हादसे न केवल जान-माल के नुकसान का कारण बनते हैं, बल्कि निर्माण गुणवत्ता, रखरखाव और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करते हैं।

बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल की घटनाएं, जैसे 2025 में पुणे और वडोदरा में हुए हादसे, इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करते हैं।वह भी तब जब देश में सबसे पुराना पुल जो आज भी लोगों और वाहनों के प्रयोग में है, वह असम का नामदांग ब्रिज है। यह पुल 1703 में अहोम राजा रुद्र सिंह द्वितीय द्वारा नामदांग नदी पर बनवाया गया था।इसकी खासियत यह है कि इसे एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है, और इसके निर्माण में चावल, अंडे, काली दाल और नींबू जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया था। यह पुल तीन शताब्दियों से अधिक समय तक भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर आज भी मजबूत स्थिति में है और उपयोग में है। तो सवाल यहीं खड़ा होता है कि आखिर हाल के बने पुल या कुछ वर्षों पहले पुल कभी बरसात में या बिना बरसात के भी हादसों के क्यों शिकार हो रहे हैं? तकनीकी जानकार तो बस यही कहते हैं कि पुलों के डिज़ाइन में तकनीकी त्रुटियाँ, जैसे गलत लोड गणना, पर्यावरणीय कारकों (जैसे भूकंप या हवा) की अनदेखी, और अपर्याप्त नींव डिज़ाइन, हादसों का कारण बनते हैं।

हाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक निर्माणाधीन पुल इस लिए चर्चित हो गया कि उसमें एक जगह 90 डिग्री का मोड़ आ गया। कुछ निलम्बन के बाद मामला फिलहाल ठंडा है। एक और उदाहरण देखिए, 2022 में गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल ढह गया, जिसमें विशेषज्ञों ने डिज़ाइन और मरम्मत में खामियों को जिम्मेदार ठहराया। एक शैक्षिक अध्ययन 2019 के अनुसार, डिज़ाइन की कमियाँ 20-25 प्रतिशत पुल हादसों में योगदान देती हैं। निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग, जैसे कमजोर सीमेंट, सरिया या अन्य सामग्री, पुलों की संरचनात्मक अखंडता को प्रभावित करता है। पुलों के निर्माण में गलत डिजाइन की बात तो होती है लेकिन गुणवत्ता पर चर्चा कम ही होती है। जबकि एक तकनीकी जानकार का कहना है कि पुल पर सड़क हादसे डिजाइन में तकनीकी गड़बड़ी से तो हो सकते हैं, लेकिन उसके ढहने के पीछे अधिकांश मामलों में निम्न गुणवत्ता ही होती है।

काबिले गौर है कि बिहार में 2024 में हुए 15 पुल हादसों में ठेकेदारों पर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री और खराब कारीगरी के आरोप लगे, उदाहरण के लिए, भागलपुर में 1,717 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा अगुवानी-सुल्तानगंज पुल तीन बार ढह चुका है, जिसे विशेषज्ञों ने खराब सामग्री और निर्माण प्रक्रिया से जोड़ा।पुलों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार डालना, जैसे भारी वाहनों या भीड़ का दबाव, ढहने का एक प्रमुख कारण है। 2022 के मोरबी हादसे में, पैदल पुल पर क्षमता से अधिक भीड़ के कारण 141 लोगों की मौत हुई। इसी तरह, बिहार के सहरसा में एक पुराना पुल ओवरलोडेड ट्रैक्टर के कारण ढह गया। शोध के अनुसार, 3-5 प्रतिशत पुल हादसे ओवरलोडिंग से संबंधित हैं। पुराने पुलों का नियमित रखरखाव न होना एक गंभीर समस्या है। कई पुल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, दशकों तक बिना निरीक्षण या मरम्मत के उपयोग में रहते हैं। 2025 में वडोदरा में गंभीरा पुल (40 वर्ष पुराना) ढहने की घटना में रखरखाव की लंबे समय से अनदेखी को कारण बताया गया। भारतीय पुल प्रबंधन (आईबीएमएस) के अनुसार, देश में 1,72,517 बड़े और छोटे पुल हैं, जिनमें से कई पुराने और जर्जर हैं।उधर नदियों में अवैध बालू खनन से पुलों की नींव कमजोर होती है, जिससे ढहने का खतरा बढ़ता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह एक आम समस्या है। उदाहरण के लिए, कोसी नदी पर बने कई पुलों के ढहने में अवैध खनन को एक कारक माना गया।

निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, जैसे लागत कम करने के लिए नियमों की अनदेखी, निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग, और अपर्याप्त निरीक्षण, हादसों का एक प्रमुख कारण है।जैसे मोरबी हादसे में, मरम्मत के बाद बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को खोलना लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण था। बिहार में 2024 में हुए हादसों में ठेकेदारों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जवाबदेही तय करने में कमी देखी गई। प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़, भारी बारिश और भूकंप, भारत में पुल ढहने का एक प्रमुख कारण हैं। नदियों में तेज प्रवाह और बाढ़ के कारण होने वाला स्काउर प्रभाव (नींव के पास मिट्टी का क्षरण) पुलों की नींव को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, 2016 में महाराष्ट्र के महाद में सावित्री नदी पर बना 100 साल पुराना पुल भारी बारिश के कारण ढह गया, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई। इसी तरह, बिहार में कोसी और गंगा जैसी नदियों पर बने कई पुल बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं।

एक शोध के अनुसार, 80 प्रतिशत से अधिक पुल हादसे प्राकृतिक कारकों से जुड़े हैं। भारत में पुलों की औसत आयु 34.5 वर्ष है, जो वैश्विक औसत (50 वर्ष) से कम है।ये भी गौरतलब है कि केवल बिहार में 2024 के हादसों में 1,200-1,700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। 2020 में एक अध्ययन किया गया था। इसका नाम था 'भारत में 1977 से 2017 तक पुलों के टूटने का विश्लेषण'। यह अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग' में प्रकाशित हुआ था। इस अध्ययन में कहा गया कि पिछले 40 सालों में 2,130 पुल ढह गए। जिनमें से अधिकांश निर्माण चरण में थीं।वहीं 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यसभा को जानकारी दी थी कि पिछले तीन सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 पुल ढह गए। इनमें से 15 पुल बने हुए थे और छह निर्माणाधीन थे।इस दौरान एक और अध्ययन सामने आया है। अध्ययन में 2,010 पुलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि भारत में पुलों के टूटने का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं। लगभग 80.3 प्रतिशत पुल प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूटे। इसके अलावा, 10.1 प्रतिशत पुल सामग्री की खराबी के कारण टूटे, जबकि 3.28 प्रतिशत पुल ओवरलोडिंग के कारण टूटे।

दरअसल देश में हादसों के बाद जांच कमेटी बनती है, जांच होती है लेकिन नतीजा कभी नहीं निकलता। कुछ निलम्बन तक कार्रवाई सिमट जाती है।भारत में पुल गिरने की घटनाएँ एक जटिल और बहुआयामी समस्या हैं, जिसमें प्राकृतिक, तकनीकी और मानवीय कारक शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है,है, दरअसल इन हादसों से बचने के लिए पुलों का नियमित निरीक्षण, परीक्षण और मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुलों की ठीक से देखभाल करेंगे, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। इन सभी हादसों से एक बात तो साफ है कि हमें पुलों की सुरक्षा को लेकर और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। हमें पुलों का नियमित निरीक्षण, परीक्षण और मरम्मत करना चाहिए। हमें पुलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलों पर ओवरलोडिंग न हो। अगर हम ये कदम उठाएंगे, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रिपोर्टिंग और बहाली के लिए सुधारात्मक उपाय ऐसी आपदाओं को कम करेंगे। शोध से पता चलता है कि भारत में पुल गिरने के प्रमुख कारणों में डिज़ाइन की कमियाँ, खराब रखरखाव, स्काउर प्रभाव, और ओवरलोडिंग शामिल हैं।लापरवाही और भ्रष्टाचार, जैसे सुरक्षा प्रमाणपत्रों की अनदेखी और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में समझौता, कई हादसों में योगदान देती प्रतीत होती हैं।

हाल के वर्षों में, जैसे 2025 में पुणे और गुजरात, और 2024 में बिहार में कई पुल ढहने की घटनाएँ हुई हैं, जो बुनियादी ढाँचे की कमजोरियों को उजागर करती हैं।यह मुद्दा जटिल है, और विभिन्न पक्षों के बीच जवाबदेही और सुधारों पर मतभेद हैं।इन हादसों को रोकने के लिए सरकार, इंजीनियरिंग समुदाय और नागरिकों को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण, नियमित रखरखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करे। केवल तभी भारत सुरक्षित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

बिहार में बड़ा खेला करने को आतुर छोटे खिलाड़ी

राजनीति

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए विमर्श गढ़े जा रहे है। बिहार में जातिवादी राजनीति ज्यादा प्रभावशाली रही है, इस नजरिए से देखे तो अधिकांश दल दो खेमों में बंटे है। यादव एवं मुस्लिम इंडी गठबंधन के वही ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी एनडीए समर्थक माने जाते है। इंडी गठबंधन की कमान राजद के हाथ में है, कांग्रेस के अतिरिक्त छोटे दलों में मुकेश साहनी की वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टियां आदि है। एनडीए गठबंधन में सरकार की कमान नीतीश बाबू के पास है, लेकिन सारथी का दायित्व बीजेपी निभा रही है। इनके अलावा चिराग पासवान, मांझी एवं कुशवाह के दल है। । दोनों गठबंधनो के अन्य दल अपनी अपनी जातियों में ताकतवर है। दो प्रमुख दल ओवैसी की एआईआईएमएस एवं प्रशांत किशोर की जन सुराज जो पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में है, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

यहां छोटे खिलाड़ियों से तात्पर्य राजनीतिक रसूख नहीं वरन वर्तमान विधान सभा में उनकी सदस्य संख्या है। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रशांत किशोर उर्फ पीके की नव गठित सुराज पार्टी का जो पहली बार विधान सभा चुनाव मैदान में है। इसके बावजूद पीके को बहुत उम्मीदें है। इसके पीछे उनके अपने तर्क एवं आत्मविश्वास है। उनकी यूएसपी एक सफल चुनावी रणनीतिकार की है। उन्होंने 2014 के बाद प्रमुख विरोधी दलों के साथ काम कर पूरे देश की राजनीति को परखा एवं पिछले तीन साल में पैदल घूम घूम कर करीब 3000 किमी यात्रा में बिहार का चप्पा चप्पा छान मारा है। गांवों वालों के साथ भोजपुरी में बात करने वाले पीके ने उच्च वर्गीय समाज से परिष्कृत भाषा में संवाद कर लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने का सफल प्रयास किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी दम पर उन्हें उम्मीद है कि बिहार की जनता उनकी पार्टी को 130/135 सीटों पर विजयी बनाकर सत्ता का ताज पहनाएगी। लेकिन भीड़ को अपना समर्थक या वोटर मान लेना मूर्खता ही होगी। उन्हें यह आशंका भी है कि वे पांच दस सीटों पर भी सिमट सकते है। इसका अर्थ कही ना कही उनके अंतर्मन में जातिवाद का प्रभाव तो है। उम्मीद है शहरी इलाकों से जहां पढ़ा लिखा वर्ग ज्यादा है, वे अच्छी संख्या में सीटे जीत सकते है। गांवों में जातिवाद ज्यादा प्रभावी होने से उनकी पार्टी के वोट कटवा होने की संभावना ज्यादा है। एम वाय समीकरण या हिंदुत्व की लहर प्रभावशाली होने पर पीके के कम सीटों पर सिमट सकते है।

पीके का नकारात्मक पक्ष उनकी अस्पष्ट विचारधारा है। उनका उच्च स्वर्ण होना बिहार की जाति वादी राजनीति में परेशानी का सबब है, जिसे वे स्वीकार नहीं करते। वे अपने भाषणों में उन्हीं वादों या बातों को दोहरा रहे है जो देहली में केजरीवाल ने अपने प्रारंभिक दौर में किए थे। केजरीवाल की कथनी एवं करनी में अंतर देहली में उनकी हार का कारण बनी थी। सवाल यह भी है कि क्या पीके बिहार की 243 सीटों के लिए साफ छबि वाले उम्मीदवार खोज पायेंगे, जो बिना धन एवं बाहु बल के चुनाव जीत सके ? यह भी देखने में आ रहा है कि इन दिनों वे वरिष्ठ पत्रकारों को इंटरव्यू के दौरान अरुचिकर प्रश्नों के जवाब देते समय तार्किक होने के बावजूद उत्तेजित या तल्ख हो जाते है, जो एक राजनेता के लिए अवगुण है। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि हंग विधानसभा की स्थिति में वे नवमी फेल तेजस्वी (उन्हीं के शब्द) को या बीमार एवं असफल प्रशासक नीतीश में से किसको अपना समर्थन देंगे।दूसरे प्रमुख खिलाड़ी औवेसी ने राष्ट्रवादी के अपने नए अवतार के बावजूद इंडी गठबंधन में शामिल होने की महत्वाकांक्षा जताई थी, जो उनकी मुस्लिम परस्त राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल है। लेकिन तेजस्वी यादव को अपने मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा है, अतः उन्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। पिछली बार उनकी पार्टी ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार बिहार से उन्हें बहुत उम्मीद है। इसलिए पिछली बार की तुलना में अधिक सीटो पर लड़ सकते है। लेकिन इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है।

तीसरे प्रमुख खिलाड़ी चिराग पासवान है, जो फिलहाल केंद्र में मंत्री है। इन दिनों चिराग पासवान बीजेपी के लिया पहेली बने हुए है। पिछले दिनों उनके द्वारा दिए गए बयानों से खासी हलचल मची हुई है। विधान सभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से उनके बारे में अलग अलग धारणाएं बन रही है। इसका सीधा सा मतलब है चुनाव में वे एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ का मानना है कि बीजेपी ने जेडीयू पर दबाव बनाने के लिए उनसे ये बयान दिलवाया है, ताकि जेडीयू की सीटों को कमकर उन्हें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटे दी जा सके। यह भी चर्चा है कि उनके और पीके बीच कुछ गुप्त समझौता है। किसी भी स्थिति में चिराग पासवान की इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी।विधान सभा चुनाव में इस बार दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारों पर ही सब कुछ निर्धारित है। महागठबंधन में तेजस्वी इतने ताकतवर बन कर उभरे है कि उन्हें मनचाही सीटे हथियाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण विरोधी रैली में जिस तरह से राहुल गांधी के सामने कन्हैया कुमार एवं पप्पू यादव को धकेल कर मंच पर चढ़ने से रोका गया उसे कांग्रेस को उसकी औकात बताना ही कहा जाएगा। पप्पू यादव राजद को तीन चार सीटों का नुकसान कर सकते है। गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में पचास सीटे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अन्य दलों को पिछली बार के आधार पर ही सीटे मिलेगी। एनडीए में इस बार सीट बंटवारे में तकलीफें ज्यादा है। जेडीयू की पिछली बार आवंटित सीटों के अनुपात में विजित सीटे बहुत कम थी, लेकिन लोकसभा में तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन अच्छा रहा था। मुस्लिम समुदाय का अच्छा समर्थन मिलना उनके लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। मगर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आने से इस बार मुस्लिम वोट छिटक सकते है। मुस्लिमों के पास इस बार जन सुराज पार्टी के रूप में एक नया विकल्प भी है। नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री होना तुरुप के इक्के का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए जेडीयू के दावों की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। ऐसा माना जा सकता है कि चुनाव नतीजों पर जेडीयू को आवंटित सीटों का बहुत असर होगा। बीजेपी की रणनीति जेडीयू को कम से कम सीटे आवंटित करने की रहेगी। पासवान को कुछ अधिक सीटे देकर संतुष्ट कर लिया जाएगा तो अन्य दल भी कुछ अधिक सीटे लेकर ही मानेंगे। यह तय है कि इनमें से अधिकांश सीटे जेडीयू के कोटे की होगी। नीतीश बाबू के स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक नाकामी भी उनके विरुद्ध जा रही है, जो एनडीए को लिए भी नुकसान कारक है।

सत्ता की सुंदरी किसका वरण करेगी इस निर्णय में औवेसी एवं प्रशांतकिशोर की भूमिका एक नया इतिहास लिख सकती है। प्रशांत किशोर, औवेसी एवं चिराग पासवान जैसे छोटे खिलाड़ी बढ़ा खेला कर जाय तो आश्चर्य नहीं होगा।

सच्ची मोहब्बत का लफड़ा

कटाक्ष

सूर्यदीप कुशवाहा

लेखक व्यंग्यकार है।

मोहब्बत का रोग है। कहां कोई निरोग है? इस रोग में बड़ा जोखिम है। जान का खतरा है। आजकल मोहब्बत की सोहबत खतरनाक है। मोहब्बत में बॉडी में सिरहन होती है और डेड बॉडी बनते देर नहीं लगती है। मोहब्बत शादी से पहले कि हो या शादी के बाद दोनों डेंजर हैं। नहीं चेते तो पीठ में खंजर है। अब जमाना बड़ा हाईटेक है। यह प्रेमिकाओं के करनामों का युग है।नीला ड्रम का भ्रम डराता है। यही ड्रम यमराज तक ले जाता है। टुकड़े वाली मोहब्बत की क्या बात और खबरों में बेबात। तुम पसंद नहीं तो कोई और सही। खैर बनाओ नहीं तो हनीमून पर जिंदगी सून कर देगी। आजकल पहाड़ों के हनीमून में दिखा खून है। बेचारे डर गए हैं दूल्हे, दुल्हन की तिरिया चरित्र में। दुल्हन है या यमराज की मौत मशीन। माशाअल्लाह ! क्या कहें हम।

मोहब्बत की नहीं जाती। यह हो जाती है। बहरहाल, डर सबको लगता है। गला सबका सूखता है। आजकल दूल्हे दुल्हन की मोहब्बत को जान अक्सर उसके मजनू से विवाह करा दे रहे हैं। वरना मरना निश्चित है। मजनू से विवाह करा बेचारे निश्चिंत हैं। धड़कन बढ़ जाती है जब पत्नी किसी से मोबाइल पर बतियाती है। यदि किसी ने टोका तो डेड बॉडी बन कर खबरों में ज़िंदा हो जाओगे इसलिए सावधान! क्योंकि सावधानी हटी तो तेरही की पूड़ी बटी। मर्दों का जीवन जोखिम भरा हो गया है। प्रेम करे की जासूसी करे। इसके बाद फल भुगते। करे तो आखिर क्या करे?

सच्ची मुच्ची मोहब्बत के हथकंडे, मारे चापड़ लगे डंडे। समझ गए बेचारे दूल्हे पंडे। उम्र बीस की हो या पचास की सब ढाई अक्षर में पड़ गई हैं। यह अंधी मोहब्बत है। ना कोई लाज परहेज है। चार बच्चों की अम्मी को भी अब्बा से नहीं बल्कि बब्बा से रूहानी मोहब्बत हो रही है और फिर शौहर को रूह बना दे रही हैं। रूहानियत की नियत में बड़ा खोट है। यह खाट खड़ी कर देती है। सच्ची मोहब्बत भी 440 बोल्ट का वॉट लगा देती है। जब वह अपने पर आती है। अंतहीन दर्दनाक कथा है। मर्द की शादीशुदा जिंदगी की व्यथा है। बेचारा नथा है। सच्ची मोहब्बत अन्यथा है। खबरों में पढ़ रहे सब कथा हैं। दुल्हन की भी कोई व्यथा होगी, तभी तो ऐसी हृदय विदारक कथा है।

भई ! झटका तगड़ा सच्ची मोहब्बत का लफड़ा। लगता है शादीशुदा बेगम को मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। शौहर की चीख से आह भी ना निकली। बड़ी शातिर हैं ये दुल्हने।आजकल बहुत खबरों में आती हैं। मर्द को डराती हैं। शादी का पंडित जी मंत्र पढ़े या मौलवी साहब निकाह पढ़े सबपे मोहब्बत का तंत्र भारी है। मोहब्बत का यंत्र सर्वत्र है। मौत का दूसरा नाम सच्ची मोहब्बत है।मोहब्बत में फना हो जाना है। मर्द को मोहब्बत की गली आना है और फिर यमलोक जाना हैं। अब ऐसी ही लोककथा बन रही है। जो प्रेरित नहीं करती है।क्या आपको भी दूल्हा बनने का शौक है। अब दूल्हा न बनना इह लोक क्योंकि आगे घर में शोक है।

दूल्हा बनने का जतन, आगे पतन है। सच्ची मोहब्बत का चक्कर में ना पड़ना। इसीलिए अनुभवी महापुरुष सन्यासी हैं। दाम्पत्य जीवन कांटों भरी राह है। बाबा बनने की सरल राह है। पहुंचे हुए एक बाबा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आदमी गरल और सन्यास आश्रम में अमृत पीता है। अब समझ गए होंगे आप साधुओं संख्या क्यों ज्यादा है? सभी आदमियों को गरल पीना संभव नहीं है। शादी का लड्डू खाकर पचाना सबके बूते की बात नहीं। शादीशुदा जीवन बीतना बलबूतों के बस की बात है। जब दुल्हन पास है तो शादी करने वालों को आस है।वरना जिंदगी नाश है। अब नए रंगरूट कह रहे हैं....विवाह न हो काश। क्योंकि जान गए हैं वो सच्ची मोहब्बत का लफड़ा और मौत ने जकड़ा।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सावन के बादलों का इंतजार सिर्फ प्रेमियों को ही नहीं रहता

व्यंग्य

मुकेश नेमा

लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

सावन के बादलों का इंतज़ार बस प्रेमियों को रहता हो ऐसी क़तई नही है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार और अफसर उनसे भी ज्यादा अधीरता से निहारते है बादलों को। बादलों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वो आएं और सड़कों को बहा ले जाएं। सड़क बनाने वाले ठेकेदार और अफसर आस्तिक होते है। भगवान भी प्रेम करता है उनसे और आमतौर पर हर साल बादल भेजना याद रखता है। सलोने बादल आते हैं। बरसते है ,और उनका रास्ता ताकती भावनाओं से भरी सड़कें बह जाती है।

सड़कें बहने के लिए ही बनाई जाती है हमारे यहाँ। पर कभी कभार अनहोनी भी होती ही हैं। कुछ ढीठ किस्म की सड़कें नही भी बहती। ऐसा ही अजीब वाकया हुआ एक शहर में। एक सड़क बादलों के मनुहार के बावजूद नही बही। दुनिया का सातवाँ आश्चर्य। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैली। हैरान जनता झुंड बना बना कर उसे देखने आई। पब्लिक को सतयुग आने का शक हुआ। लोगों ने आँखें मल मल कर देखा बिना बही सड़क को। एक दूसरे को चिकोटी काट कर तस्दीक की कि कहीं वो सपना तो नही देख रहे। और जो चीज देख रहे हैं वो सड़क ही है या कुछ और है। फिर जनता हो हो कर हँसी और उसने सड़क बनाने वाले अफसर और ठेकेदार को गधा करार दिया।

खबर सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार महकमे तक भी पहुँची। संबंधित अफसर को बाक़ी अफसरों ने दया भाव से देखा। सब हँसे उस पर। वो अपनी ग़ैरज़िम्मेदारी पर शर्मिंदा हुआ। उसने फौरन सड़क बनाने वाले ठेकेदार को तामील किया। ठेकेदार आया। घबराया और आँखें नीचे किए रहा।

साहब अनमना है बहुत। शर्मा ऐसी उम्मीद थी नही तुमसे। ठेकेदार सचमुच शर्मिंदा है। दुखी है अपने ही पेट पर लात मारने के लिए। सर मैंने डांटा है अपने बंदों को।

साहब मायूस भी है। ये क्या कर बैठे तुम ? बिना बही सड़कें साख खराब करती हैं। अब बड़े अफसर तुम्हारे साथ मुझे भी नौसिखिया मानेंगे। सबका नुकसान कर दिया तुमने। नई नई नौकरी है मेरी।मुझे डर है कहीं प्रोबेशन पीरियड न बढ़ा दिया जाए मेरा।

अफसर भी नया था और ठेकेदार भी। ठेकेदार के मरे बाप भी ठेकेदार थे सो लड़का भी ठेकेदार हुआ और फिर नासमझी में वो सड़क बना बैठा जो बहने के लिए तैयार नही हुई।

कम से कम अपने पिताजी की इज्जत की ही सोच लेते। वो इतने शरीफ थे कि बादलों को जहमत देने से भी बचते थे। कागज़ों पर ही सड़के बना कर बहा देने के लिए मशहूर थे। और ये तुम्हारा किया धरा है। न सड़क बही न उसमें गड्डे हुए। सड़कें बहेगी नही तो हमारी तुम्हारी जरूरत क्या रह जाएगी ?

सर आदमी गलती कर के ही सीखता है। अब आगे कभी ऐसी गलती हो जाए तो आपका जूता और मेरा सर।

सब हँस रहे है यार।मन लगाकर काम किया नही तुमने।

सर अब ये गलती दोबारा नही होगी।

बादलों की पेशी भी हुई इन्द्र के सामने।

कामचोरी सीख आए धरती पर जाकर। उस सड़क को राजी नही कर पाए बहने के लिए ?

सर । हमने तो पूरी कोशिश की उसे मनाने की। पर वो जिद्दी और ईमानदार थी।

ये अजीब बात बताई तुमने। सड़कें तो मरी जाती है बहने के लिए। तुम्हीं ढंग ये इन्प्रेस कर नही पाए उसे। निकम्मे हो तुम। यदि हम सड़कें ही न बहा सके तो कौन भरोसा करेगा हम पर ?सर अगली बार फिर कोशिश करेंगे हम। उस घमंडी सड़क का सर झुका कर रहेंगे।

इन्द्र नाराज थे सो बादल दफ़ा किए गए।

खैर। जो होना था हो चुका। एक जिद्दी सड़क ने बहने से इनकार कर बादलों ,ठेकेदारों और अफसरों सबके कैरियर को खतरे में डाल दिया है। बादल मुँह छुपाए फिर रहे है और अफसर और ठेकेदार गमगीन है।ये शाम को गम गलत करेंगे मिलकर। आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। उम्मीद की जाना चाहिए कि बादल हिम्मत कर दोबारा बरसेंगे। मना लेंगे सड़क को। अगली बार उसे बहाने में कामयाब होंगे। ये जरूरी भी है ताकि बादलों अफसरों और ठेकेदारों की साख ,उनका आत्मसम्मान और समाज में उनकी इज्जत दोबारा बहाल हो सके।

धर्मांतरण

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

विदेशी फंडिंग और सामाजिक विघटन का षड्यंत्र

धर्म किसी भी समाज की आत्मा होता है, लेकिन जब धर्म का प्रयोग 'धंधे' में बदल जाए तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा उजागर किए गए एक बड़े धर्मांतरण रैकेट ने यही भयावह सच्चाई हमारे सामने रखी है। कथित रूप से 'छांगरू बाबा' उर्फ जमशेदुद्दीन के नेतृत्व में यह गिरोह न केवल भोले-भाले लोगों का धर्मांतरण कर रहा था, बल्कि इसके पीछे एक व्यवस्थित नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और जातिगत लक्ष्य निर्धारण भी शामिल था।

जिस प्रकार से इस रैकेट की कार्यप्रणाली सामने आई है, वह धर्मांतरण को एक सुनियोजित व्यवसाय के रूप में प्रकट करती है। यह कोई व्यक्तिगत आस्था का निर्णय नहीं, बल्कि विदेशी पैसों से संचालित एक मिशन था- जिसमें धर्म, जाति, स्त्री और समाज को एक वस्तु की तरह देखा गया। एफआईआर और जांच रिपोर्ट के अनुसार, धर्मांतरण के लिए बाकायदा 'रेट काड' था। ऊंची जाति की लड़कियों के लिए धर्मांतरण की दर 15-16 लाख रुपये तक थी, जबकि अन्य लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपये। सोचिए, जब धर्म को भी जाति और लिंग के आधार पर मूल्यांकित किया जाने लगे, तो वह किस स्तर तक गिरावट का प्रतीक बनता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रैकेट के पास 40 बैंक खाते थे जिनमें विदेशों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई। यह रकम किसके इशारे पर भेजी गई, किन उद्देश्यों के लिए, और किन देशों से - यह सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों के नहीं, पूरे देश के हैं। क्या यह केवल धर्मांतरण के लिए था या इसके पीछे कोई और बड़ा वैश्विक, राजनीतिक या वैचारिक षड्यंत्र भी छिपा है?

इस रैकेट की कार्यशैली में सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया गया। वीडियो, मोटिवेशनल भाषण, 'इस्लाम कबूल करने से मिली राहत' जैसे फर्जी वीडियो वायरल कर कमजोर तबकों को बरगलाया गया। पहले मानसिक रूप से प्रभावित किया गया, फिर आर्थिक लालच दिया गया और अंत में जबरन धर्मांतरण। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा है - जहां पहले मस्तिष्क जीता जाता है, फिर शरीर। और सबसे दुखद यह कि इसे धर्म का नाम दिया गया।

इस प्रकरण में बलरामपुर जिले के एक पूरे परिवार के धर्मांतरण की पुष्टि हुई है। वहां महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई एक अपवाद नहीं, बल्कि उसी पैटर्न का हिस्सा है - जिसमें ग्रामीण, अशिक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया जाता है। यह सामाजिक असमानता का शोषण है। जब राज्य, समाज और प्रशासन इन परिवारों की रक्षा नहीं कर पाते, तो ऐसे गिरोह अपना मकड़जाल फैलाते हैं।

इस रैकेट का सबसे खतरनाक पहलू था - जातिगत दर निर्धारण। ऊंची जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए अधिक पैसा दिया जाता था। इसका मतलब है कि धर्मांतरण सिर्फ धर्म का नहीं, जाति-सामाजिक संरचना को तोड़ने का औजार भी बन चुका है। यह न केवल हिंदू समाज को कमजोर करने की चाल है, बल्कि राष्ट्र को आंतरिक रूप से विखंडित करने की भी रणनीति है।

इस मामले पर तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी वर्ग चुप है। वही वर्ग जो 'धर्मनिरपेक्षता' की दुहाई देता है, 'संविधान की आत्मा' की बात करता है, आज गूंगा बना बैठा है। क्यों? क्या धर्मांतरण को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया गया है? क्या किसी गरीब, दलित, महिला या आदिवासी का जबरन धर्म बदलवाना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अगर किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने से किसी को आपत्ति है, तो उस पर शोर मचता है, लेकिन जब उसी दलित को पैसों से धर्म बदलवाया जाता है तो कोई नहीं बोलता। यह मौन स्वयं एक अपराध है।

यह भी गौरतलब है कि ऐसे मामलों पर राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक की राजनीति के कारण खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देते। अल्पसंख्यकों की 'संवेदनशीलता' के नाम पर ऐसे राष्ट्रघातक कृत्यों को नजरअंदाज किया जाता है। सवाल यह है कि क्या देश की अखंडता और सामाजिक समरसता वोट बैंक से भी छोटी हो गई है? अगर कोई हिंदू संगठन धर्मांतरण रोकने की बात करता है तो उसे कट्टरपंथी कह दिया जाता है, लेकिन जब धर्मांतरण के नाम पर विदेशी पैसा आकर समाज को तोड़ता है, तो सब चुप हो जाते हैं।

यह मामला अकेला नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सामाजिक दुर्बलता, आर्थिक मजबूरी और शिक्षा की कमी का लाभ उठाकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और मजबूत बनाना चाहिए। विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र को सशक्त करना चाहिए। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समाज को आत्मनिर्भर और सजग बनाना जरूरी है।

धर्म आत्मा का विषय है, उसे सौदेबाज़ी का औजार बनाना न केवल अपराध है, बल्कि मानवता का भी अपमान है। धर्मांतरण जब व्यक्तिगत चेतना से नहीं, लालच, भय या फरेब से होता है, तो वह धर्म नहीं, शोषण होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम धर्मांतरण की आड़ में चल रहे इन संगठित अपराधों को पहचानें, उनका विरोध करें और समाज को ऐसी गतिविधियों से बचाने के लिए संगठित प्रयास करें। धर्म को न बेचे, न खरीदें - बल्कि समझें, आत्मसात करें और उसकी गरिमा को बचाए रखें।

मेट्रो इन दिनों- संगीत और भावनाओं का रोलर कोस्टर

फिल्म

भारती पंडित

समीक्षक

मेट्रो इन दिनों को अनुराग बसु की फिल्म लाइफ इन मेट्रो (2007) का अगला भाग कहा जा सकता है। दोनों फिल्में एक ही विषय पर अलग-अलग तासीर की बनी फिल्में हैं जो जीवन में प्यार और रिश्तों की ओवरहालिंग पर बात करती हैं। मज़े की बात यह है कि पुरानी मेट्रो में भी विद्यमान रिश्तों को बनाए रखने की बात थी, नई फिल्म भी इसी संदेश के साथ जाती नज़र आती है। दोनों ही फिल्में अपनी जीवन की खुशी के लिए किसी साहसिक निर्णय की वकालत नहीं करती, या शायद यह मानती है कि परिवार नामक इकाई का हर हाल में बने रहना आवश्यक होता है खैर।

मेट्रो इन दिनों को देखते हुए किसी उपन्यास को पढ़ने, देखने और जीने का सा अहसास होगा। पहली फिल्म की ही तरह इस फिल्म में भी कई कहानियाँ गुथी हुई हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे इन चार महानगरों में बसी चार पीढ़ियों के पात्रों की दौड़ती-भागती ज़िंदगी के बीच रिश्तों की उलझनें, गलतफहमियों और कशमकश को समेटती यह फिल्म पूरे पौने तीन घंटे आपको बाँधे रखती है। हर रिश्ता अपने आप में उलझा हुआ है। शादीशुदा जोड़े रिश्ते के बासीपन से उकताए हुए हैं, उनकी शादी से प्यार, रोमांच, रोमांस सब गायब है...पुरुष डेटिंग एप पर सुकून खोज रहे हैं तो महिलाएँ उन पर नज़र रखने, अपने अधूरे सपनों को फिर से जीने और बाहर कहीं खुशी खोजने की जद्दो जहद में लगी हुई हैं। नई पीढ़ी यानी एकदम युवा शादी के रिश्ते में अर्थ खोजना चाहते हैं तो किशोर अपनी यौनिक पहचान की खोज में उलझे हुए हैं।

एक कहानी आदित्य और श्रुति की है, श्रुति आदित्य के गायक बनने के सपने के लिए अपना कैरियर छोड़ती है, पर सफलता का रास्ता इतना आसान कहाँ है। दूसरी कहानी काजोल (कोंकणा सेन) और मोंटी की जिनकी शादी में बस खिचखिच बची है और दोनों ही इससे भाग रहे हैं, उनकी बेटी अपनी यौनिक पहचान की खोज में है...तीसरी कहानी काजोल की बहन चुमकी की है जो दब्बूपन से दो चार हो रही है, उत्पीड़न सह रही है और अब शादी के निर्णय की ऊहापोह में उलझी है। एक कहानी वरिष्ठ पीढ़ी की शिबानी और परिमल की है...परिमल अपने प्यार को रोक न पाया और शिबानी अपनी शादी में बस समझौते ही करती रही।इन सबके बीच ताज़ी हवा सा है पार्थ, ट्रैवल ब्लॉगर जिसके जीवन का मूलमंत्र ही है कि जीवन में वह करो जिससे खुशी मिले, जीवन एक ही बार मिला है और उसमें खुश रहने का अधिकार सबको है।

इस फिल्म में अनुराग ने एक अभिनव प्रयोग किया है, गीतों के जरिए पात्रों को अभिव्यक्त करने का...

गीतों के रूप में होती बातचीत अच्छी लगती है, मज़ा देती है और नयापन लाती है। सच मानो तो किसी थिएटर में बैठकर ओपेरा का आनंद लेने जैसा महसूस होता है। हाँ, कुछ दृश्यों में गीत-संगीत इतना तेज़ है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति को मंद कर देता है। इसके चलते कुछ दृश्य जिनमें भावनाएँ महत्वपूर्ण थीं, वह उस तीव्रता से अनुभूत नहीं हो पाती। हमारे समाज में शादी एक आवश्यक बंधन है जिसे मनचाहे या अनचाहे निभाना ही पड़ता है। जब एक सी दिनचर्या, एक सा काम, एक सा भोजन अरुचि पैदा कर सकता है तो एक सा रिश्ता ऊबाऊ होगा ही, तो यह सारी जद्दोजहद इस बासी हो रहे रिश्ते को दिखावे में ही सही ताजा बनाए रखने की है। फिल्म में पार्थ कहता है, शादी और कुछ सिखाए या न सिखाए, झूठ बोलना और एक्टिंग करना बेहतरी से सिखाती है। सच ही है न, और इसकी सत्यता आप अपने आसपास विद्यमान रिश्तों को देखकर जाँच सकते हैं। शादी में समस्या है यह मानने की बजाय सारा समाज हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक है इसी दिखावे में लगा रहता है।शादी एक कमिटमेंट है और इसे निभाने के लिए दोनों को ईमानदार होना जरूरी है। यह कमिटमेंट केवल शारीरिक ही नहीं है, मानसिक और भावनात्मक भी है। फिल्म में दूसरा मौका देने का समर्थन किया गया है पर दूसरा मौका केवल पुरुषों को ही मिला है, स्त्री द्वारा दिया गया है। यदि यही मौका स्त्री माँगती तो मिलता क्या?

मेरा यहाँ यह भी मानना है कि यदि शादी में प्यार नहीं है, केवल समझौता ही है और वह भी एक ही पक्ष से ही अपेक्षित है, तो उस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना जरूरी है। प्रेम को जबरन लाया नहीं जा सकता, साथ रहते हुए एक-दूसरे की आदत हो जाती है जिसे अक्सर प्रेम समझ लिया जाता है। इसलिए प्रेम और आदत के बीच के फर्क को समझना भी जरूरी है।

यह फिल्म धीरे से ही सही मगर रिश्ते में स्पेस देने की भी बात करती है। हमारे यहाँ शादी के बाद अकेले रहने की इच्छा करना गुनाह समान है। हमारे समाज में समझ यही है कि शादी के बाद पार्टनर को हमेशा एक-दूसरे से चिपके रहना चाहिए, हर काम साथ-साथ हो, उनकी दुनिया एक-दूसरे के आसपास ही हो और इसके चलते लोग अपने दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, सामाजिक जीवन से दूर हो जाते हैं और यही से मुश्किलों की शुरुआत होती है जब बात करने वाला कोई नहीं रहता, समस्या सुनने वाला कोई नहीं रहता...

मध्यांतर के बाद फिल्म के कुछ हिस्से अनायास खींचे हुए लगते हैं, हालांकि फिल्म की गति तेज़ होने से इतना फर्क नहीं पड़ता।

अभिनय की बात करें तो हर पात्र अपने आप में खरा है। अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकणा, पंकज त्रिपाठी को तो किसी पहचान की जरूरत है नहीं, मिर्जापुर वाले अली फज़ल, आदित्य राय कपूर, फातिमा साना और सारा अली भी शानदार लगी है। गीत-संगीत शानदार है, कुछ गीत तो बेहद सुंदर बन पड़े हैं जैसे और मुहब्बत कितनी करूँ, मन ये मेरा, दिल का क्या.... प्रीतम का संगीत शानदार है, उन्हें इम्तियाज़ और अनुराग के साथ स्क्रीन पर गाते हुए देखना अच्छा लगता है।

कैमरे के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी मगर क्लोज़ अप और दूरी के शॉट्स दोनों ही अच्छे बन पड़े हैं।

अनुराग बसु का निर्देशन पहले हिस्से में बेहद कसा हुआ हुआ और शानदार है, दूसरे हिस्से में थोड़ी और कसावट की दरकार थी पर शानदार अभिनय, कसी हुई स्क्रिप्ट इस कमी को छिपा लेती है।

बहरहाल इस फिल्म को जरूर देखिए, अपने प्रेमी-प्रेमिका के साथ, पार्टनर के साथ, युवा होते बच्चों के साथ भी और अपने रिश्तों की बुनावट पर फिर विचार कीजिए।

न परी जैसी, न महक जैसी उनकी करतूत

सामयिक

सुरेश सौरभ

ये कितना दुखद और चिन्ता का विषय है कि आज की युवा पीढ़ी को रील्स बनाने की इस कदर दीवानगी है कि वह अच्छे-बुरे कांटेंट पर भी जरा भी विचार नहीं करती। उत्तर प्रदेश के संभल में परी, महक और उसके साथियों द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना, पुलिस का सराहनीय कदम कहा जा सकता है।

बकौल,पुलिस अश्लील कांटेंट से उन्हें बीस-पच्चीस हजार प्रतिमाह कमाई होती थी। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर गाली-गलौच भरे वीडियो प्रसारित किये। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ के अरविन्द नाम के एक युवक को भी पुलिस सोशल मीडिया पर अश्लील कांटेंट प्रसारित करने के लिए जेल भेज चुकी है।

यह बड़ा सवाल है कि आज का किशोर युवा तथा हर वर्ग का व्यक्ति आखिर तात्कालिक लोकप्रियता क्यों पाना चाहता है? इसके लिए चाहे उसे सड़क पर नाचना-गाना पड़े, चाहे गालियां बकनी पड़े, चाहे फेंक न्यूज ही बनानी पड़े। कई बार तो रील बनाते-बनाते लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं, घायल हो जाते हैं, या रील्स बनाने से, जब उनके परिवारी जनों के द्वारा मना किया जाता है तो, वह अपने परिवार के लिए ही आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ऐसी तमाम खबरें प्रकाशन में आती रहती हैं। पुलिस का संभल की लड़कियों बारे में कहना है कि वह कम पढ़ी-लिखीं थीं, इसलिए सस्ती लोकप्रियता और व्यूस से कमाई के लिए अश्लीलता का उन्होंने सहारा लिया। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से पढ़े-लिखे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पत्रकर, लेखक, नेता मंत्री तक धड़ाधड़ बेवजह रील्स बनाने का शौक पाले पड़े हैं। एक प्रोफेसर साहब ने तो पीटकर सुर्ती देते हुए अपना वीडियो अपलोड किया। अब उनके बच्चे उनसे क्या शिक्षा लेंगे। बौद्धिक वर्ग यह भी नहीं देखता कि उनकी रील्स की विषय-वस्तु क्या है? इसका संदेश क्या जायेगा? आभासी दुनिया में लोकप्रियता पाने के लिए हर वर्ग लालायित है, पर यह भी ध्यान रखा जाए कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को किसी तरह से विस्मृत न किया जाये। आभासी दुनिया की दीवानगी परिवार सामाज और देश के लिए घातक न बने। यह जिम्मेदारी देश के सभी जागरूक नागरिकों की है। लाखों वीडियो प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं पुलिस किस-किस का मूल्यांकन करेगी। यह जिम्मेदारी महक और परी जैसी लड़कियों के अभिभावकों की भी है कि वह अपने बच्चों को संस्कारित करें। आज भले ही शिवानी जैसी कुछ लड़कियां सोशल मीडिया के माध्यम से बिग बॉस जैसे बड़े मंचों से थोड़ी सी दौलत शोहरत पा गयीं हो, पर बहुत से लोग गफलत में पड़कर परी और महक की तरह कुमार्ग पर जाकर अपना भविष्य ही खराब कर रहे हैं। बेकारी अशिक्षा में आज का युवा दिगभ्रमित हो रहा है, उसे आभासी दुनिया की सस्ती तात्कालिक लोकप्रियता को छोड़कर अच्छे गुरुओं और पुस्तकालय की ओर रूख करना चाहिए। कौशल विकास से अपनी प्रतिभा को चमकाना चाहिए, सूरत से ज्यादा उन्हें सीरत चमकाने की जरूरत है।

अंकुरण

सत्येन्द्र पाण्डेय

प्रभाति बारिक- घनघोर अंधेरों के बीच उजाले की एक किरण

प्रभाति का मतलब होता है- सुबह। कुछ इलाकों में सुबह- सुबह गाए जाने वाले गीतों को भी प्रभाति कहा जाता है। सुबह के पहले रात होती है, अक्सर घनघोर अँधेरे वाली रात। इसी अँधेरे के बीच से उम्मीद का सूरज निकलता है और प्रभात के समय सब कुछ उजागर हो जाता है। रुका हुआ जीवन एक बार फिर से शुरू हो जाता है। अँधेरे समय में इसी तरह के उजाले की एक किरण है- प्रभाति बारिक। एक समय था जब उनके अपने जीवन में अँधेरे गहराए हुए थे और कोई आश्चर्य नहीं कि और कोई होता तो हिम्मत हार जाता लेकिन प्रभाति ने न तो हिम्मत हारी और न सुबह का इंतजार किया बल्कि वे पूरी ताकत से उजाले के प्रसार के लिए जुट गईं और उन्होंने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि हजारों महिलाओं के लिए भी वे एक उम्मीद का केन्द्र और बदलाव का संबल बन गई हैं।

प्रभाति का जन्म उड़ीसा के संबलपुर जिले के हीराकुद कस्बे में हुआ था जो उस समय तो एक गाँव ही था लेकिन आज शहर होने की तरफ बढ़ रहा है। आप जानते ही हैं कि हीराकुद में भारत का सबसे लम्बा बाँध है जो इस पूरे इलाके की पहचान है। हीराकुद बाँध से बिजली बनी और सिंचाई के लिए भरपूर पानी भी मिला लेकिन आसपास का इलाका फिर भी गरीब रह गया। इन्ही गरीब परिवारों में से एक था- प्रभाति बारिक का परिवार जो दो पीढ़ी पहले उड़ीसा के ही बालांगीर जिले से पलायन करके संबलपुर आया था कि रोजी-रोटी कमाने का कोई जरिया बन सके। पलायन न केवल उस समय बल्कि आज भी उडीसा की एक पहचान है। बहरहाल, रोजी-रोटी का जरिया बना तो सही लेकिन बहुत देर तक कायम नहीं रह सका। प्रभाति के पिता एल्युमिनियम इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन एक दिन नौकरी छूट गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय प्रभाति हाई स्कूल की पढाई कर रही थीं। पढाई छूटने का खतरा उत्पन्न हो गया।

प्रभाति अपने चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनसे छोटे दो भाई और एक बहन थीं। जाहिर है उनके ऊपर जिम्मेवारी और दवाब दोनों सबसे ज्यादा थे। इसके पहले भी वे अपनी पढाई के साथ-साथ अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश में अपनी माँ की भरपूर मदद करती थीं। पिता की नौकरी छूट जाने के बाद और मुश्किल हो गई। पिता ने आसपास मजदूरी करना शुरू कर दिया लेकिन जाहिर है, आमदनी तो घट ही गई थी। इस हालत में उनके सामने दूसरी लड़कियों की तरह पढाई छोड़ देने का आसान विकल्प मौजूद था लेकिन उन्होंने तो अपने मन में कुछ और ही ठान रखा था। उन्होंने सपने देखे थे और वे उन सपनों को हर हाल में पूरा करना चाहती थीं। ये सपने सिर्फ उनके अपने बारे में नहीं थे बल्कि पूरे परिवार के लिए थे। इस आयु में भी उनको समझ में आ गया था कि केवल शिक्षा ही उनके परिवार के लिए बेहतर भविष्य का दरवाज़ा खोल सकती है। इसलिए लिए खुद पढना बहुत जरुरी था। इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके घर में तो इतनी जगह नहीं थी कि बच्चों को बिठा सकें, इसलिए वे बच्चों के ही घर जाकर उन्हें पढ़ाती थीं। इसके लिए उन्हें रोज मीलों पैदल चलना पड़ता था।

लेकिन उनकी इस मेहनत ने उनके लिए कॉलेज जाने का रास्ता तैयार किया जो उनके परिवार में कभी न देखे जा

सकने वाला सपना था। जब वह कॉलेज में आई तो एक नई दुनिया से साक्षात्कार हुआ। वहां उन्हें अपने जैसी अनेक लड़कियां मिली और दोस्त बनी- सपनों और उम्मीदों से भरी हुई लेकिन गरीबी और वंचना की शिकार। ऊपर से लड़की होने की मुश्किलें, जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का सामना करती हुईं। वे अक्सर सोचती और अपने दोस्तों से सवाल करती कि क्यों लड़कियों को लड़कों की तरह समान अवसर नहीं मिलते और क्यों उनका महत्व उनकी जाति, धर्म अथवा आर्थिक स्थिति से तय होता है? इस तरह की जिज्ञासाओं के बीच उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढाई पूरी की, सिर्फ अपने दम पर। वे बताती हैं कि उनकी पूरी पढाई के दौरान उन्हें सरकार या रिश्तेदारों की तरफ से कभी एक चाक या पेन्सिल भी हासिल नहीं हुई। सब कुछ अपने दम पर किया।

ग्रेजुएट होते ही उन्होंने परिवार की बढती जरूरतों के मद्देनजर एक सामाजिक संस्था में फील्ड समन्वयक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस नौकरी ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का अवसर और आत्मविश्वास प्रदान किया। उनके छोटे भाई बहनों की पढाई अच्छे से हो सकी जिनमे से दो आज शासकीय सेवा में हैं और एक भाई अपना व्यवसाय कर रहे हैं। संस्था में काम करते हुए सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं के समूह बनाना शुरू किया और 250 समूहों के माध्यम से लगभग 5000 महिलाओं के जीवन में सांगठनिक प्रक्रियाओं, आजीविका से जुडाव और घरेलु हिंसा आदि मुद्दों पर जागरूकता के माध्यम से बदलाव लाने में सफल रही।

लेकिन परिवार पर समाज का दवाब बढ़ रहा था उनके विवाह के लिए। 2007 में झारखण्ड के जमशेदपुर में उनकी शादी हो गई। यह विवाह प्रभाति जी के लिए एक बुरा सपना साबित हुई क्योंकि एक ओर तो उनकी नौकरी छूट गई और आर्थिक आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, दूसरे शादी के तुरंत बाद से ही घरेलू हिंसा का सामना करना शुरू हो गया जो लगातार बढ़ता ही चला गया। अगले साल बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बहादुरीपूर्ण निर्णय लेते हुए इस अमानवीय जीवन से बाहर निकलकर अपने घर वापिस लौटने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपनी आजीविका सुनिश्चित करती रहीं।

इस बीच वे ग्राम स्वराज विकास समिति नामक संस्था से जुड़ गई और जल्दी ही उन्हें इसका सचिव भी बना दिया गया। लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं थी बल्कि जिम्मेवारी ही थी क्योंकि संस्था बहुत पहले गठित हुई थी परन्तु लम्बे समय से निष्क्रिय थी और प्रभाति के पद सँभालने के कुछ समय बाद ही संस्था का गठन करने वाले बुजुर्ग सज्जन का देहांत हो गया और पूरी जिम्मेवारी इनके कन्धों पर ही आ पड़ी। वे अपने कामकाज के साथ इसे भी संभालती रहीं। वे कहती हैं कि नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्डिया की अंकुरण परियोजना ने न केवल उन्हें इस दुविधा से उबारा और संस्था को दोबारा सक्रिय करने में सहयोग प्रदान किया बल्कि उनकी अपनी नेतृत्व क्षमता, संचार और मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण में भी बहुत सकारात्मक सहयोग प्रदान किया।

आज प्रभाति बारिक एक सक्षम महिला नेतृत्व के रूप में न सिर्फ अपने क्षेत्र और राज्य में एक विशेष पहचान रखती हैं बल्कि उनकी प्रेरणा, सहयोग और संस्थागत मदद से सैकड़ों महिलाएं, किशोरियां और युवतियां अपने सपनों को नयी उड़ान देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करती हुई अपनी बेटी के लिए भी एक आदर्श हैं।

पत्रकारिता पर हमेशा संकट रहा है, संघर्ष पत्रकारों की नियति : मंत्री पटेल

धार जिला पत्रकार संघ का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन शब्द समागम- 2025

धार। पत्रकारिता पर हमेशा संकट रहा है, लेकिन यह उनकी नियती है। यह राह उन्होंने स्वयं चुनी है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब रास्ता चुनना पड़ता है। पत्रकारों को सत्य और सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए। सत्य प्रस्तुति के लिए है, स्तुति के लिए नहीं। पत्रकारों के लिए जरूरी है वह संघर्ष करे पर उसके लिए अपनी जमीन न छोडे। इस समय पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक बडा मुद्दा है। धार जिला पत्रकार संघ ने इस आवश्यकता को समझा है। यह बात बुधवार को धार जिला पत्रकार संघ के शब्द समागम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा कि पत्रकार शब्दों से खेले पर संभलकर। पत्रकार और पत्रकारिता गहरे संकट में है क्योंकि पत्रकारिता के लिए जरूरी संविधान खूद संकट में है। संविधान को बचाना है तो पत्रकारिता को जिंदा रखना पडेगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री पटेल ने कहा कि विश्वास का संकट हर कहीं है, राजनीति में सबसे ज्यादा। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे आडम्बर छोड़े, इस समाज में प्रश्न जीवित रहने का नहीं है आवश्यकता सीमित हो तो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकता है। आडम्बर के कारण हम संकट में घिरते है। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दे। राजनीति के समान पत्रकारिता भी सेवा के लिए है व्यापार के लिए नही। मैंने अपने गुरू का आदेश मानकर राजनीति को सेवा ही समझा है। उन्होंने अशोक वानखेडे के तीखे हमलों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 के पहले तो राजनेताओं पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। कुछ बातों का जवाब समय देता है और कुछ का इतिहास।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 11 साल में काफी विकास हुआ है। धार जिला भी इसमें शामिल है। धार जिले के पत्रकार काफी सजग है उन्होंने पं छोटू शास्त्री को कार्यक्रम के लिए बधाई दी।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

कार्यक्रम के अंत में मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।

लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता का जिंदा रहना जरूरी : वानखेडे

मुख्य वक्ता वानखेडे ने कहा कि पत्रकारिता सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र में ही जिंदा है। शहर की पत्रकारिता केवल औपचारिता रह गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार केवल प्रामाणिक खबरे ही दे लगातार रिसर्च करे। रिसर्च कभी बेकार नहीं जाती। हमारे लिए सबसे बडा रिवार्ड जो है वह आम लोगों द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखे। वैसे भी पत्रकार विपक्ष का मित्र होता है। पत्रकारिता में ह्युमन टच जरूरी है। मंत्री पटेल से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वे राजनीति में दुलर्भ व्यक्तित्व है। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने धार जिला पत्रकार संघ को सुझाव दिया कि वह पत्रकारों अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम बनाए वे इसमें मदद करने के लिए तैयार है। पत्रकार जनसमस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण करते है यह अनुकणीय काम है।एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि छोटे अखबार भी प्रशासन में बडा सुधार कर सकते है। उन्होने एक छोटे अखबार की खबर के आधार पर जिले में पुलिसकर्मियों के तबादले किए। इसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों के तबादले हुए जिसके अच्छे परिणाम भी रहे।विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार, भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल व कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरदेवसिंह जाट ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सुबह सवेरे के संपादक हेमंत पाल भी मंचासीन थे।

'धार की धड़कन' का हुआ विमोचन, 800 से अधिक पत्रकारों को प्रदान हुई 10-10 लाख की बीमा पॉलिसी'

धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प. छोटू शास्त्री ने कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा कि शब्द समागम 10 वर्ष से निरंतर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पत्रकार साथियों की चिंता करते है। उनके लिए दो लाख रूपए की बीमा पॉलिसी देने का काम शुरू किया था जिसकी राशि अब दस लाख रूपए हो गई है। इस वर्ष 800 पत्रकारों को यह बीमा पॉलिसी भेट कर रहे है।

सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर वरिष्ठ पत्रकार स्व. राजेन्द्र माथुर, स्व. कृष्णलाल शर्मा, स्व. अरविंद काशिव के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्जवलित कर शब्द समागम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प. छोटू शास्त्री एवं महासचिव प्रदीप अगाल सहित उपस्थित पत्रकारों ने किया। इस अवसर पर वार्षिक स्मारिका 'धार की धडकन' का विमोचन एवं जिले के 800 पत्रकारों को 10-10 लाख रूपए की बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण शर्मा एवं धार जिला पत्रकार संघ के महासचिव प्रदीप अगाल ने किया। आभार जिला पंत्रकार संघ की संरक्षक पुष्पा शर्मा ने माना।

अवैध कट्टे के साथ आदतन अपराधी गिरफ्तार

बैतूल/आमला। आमला थाना पुलिस ने निमझिरी तिराहे से एक शातिर अपराधी को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में चल रहे अवैध हथियार विरोधी अभियान के तहत की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आमला पुलिस को पता चला कि हसलपुर क्षेत्र के पास निमझिरी तिराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम ताईखेड़ा निवासी पिंटू खातरकर (38) पिता रामदयाल खातरकर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया। आमला थाने में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध क्रमांक 477/25 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही काफी लंबा है। मुलताई थाने में उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और संभावित साथियों की जानकारी जुटा रही है।

चलती ट्रेन से गिरा युवक, दोनों पैर कटे

बैतूल। बैतूल रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने से एक युवक

गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा स्टेशन के आगे अंडरब्रिज के पास हुआ, जहां युवक के दोनों पैर ट्रेन से कट गए। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक धार जिले के अमझेरा गांव का रहने वाला है। जितेंद्र मंडलोई अपने बहनोई के साथ संघमित्रा एक्सप्रेस से घोड़ाडोंगरी से बैतूल आ रहा था। घटना के चश्मदीद और युवक के बहनोई प्रदीप चौधरी ने बताया कि हादसे के वक्त वे दोनों ट्रेन के गेट पर खड़े थे। जैसे ही ट्रेन बैतूल स्टेशन के पास धीमी हुई, किसी ने अचानक उन्हें पीछे से धक्का दिया। प्रदीप किसी तरह खुद को बचा पाए, लेकिन उनका साथी नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। हालांकि घायल युवक ने बयान में कहा कि उसे याद नहीं कि धक्का दिया गया या वह खुद गिरा। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी प्रभारी रविश कुमार बल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया। युवक को आईसीयू में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह हादसा था या जानबूझकर किसी ने धक्का दिया।

नर्मदापुरम आईजी पहुंचे बैतूलबाजार के सांदीपनी स्कूल

बच्चों को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ

बैतूल। प्रदेशभर में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत बुधवार को बैतूलबाजार स्थित सांदीपनी स्कूल में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदापुरम रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से आरंभ हुए इस आयोजन में स्कूल के छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण, नगर परिषद के जनप्रतिनिधि एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया ने छात्रों को संबोधित करते कहा कि भारत में नशे के कारण प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ युवा प्रभावित होते हैं। बैतूल जिले में भी 1 जनवरी 2025 से अब तक 20 नारकोटिक्स प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 9 मामले गांजा और 11 मामले अफीम से संबंधित हैं। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में की जा रही अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया है, जो वर्ष

2021 से संचालित थी। एसपी ने बताया कि अफीम एक ऐसा मादक पदार्थ है जिससे अन्य अनेक घातक ड्रग्स बनाए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नशे के प्रभाव में आकर 78 नाबालिग बच्चों ने अपराध किए हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें, पढ़ाई में मन लगाएं और देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।

आईजी ने दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ

आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने भी बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और कहा कि यदि आपके आस-पास कोई व्यक्ति नशा करता है, तो उसे समझाइए और रोकिए। उन्होंने उपस्थित सभी बच्चों व जनप्रतिनिधियों को नशे से दूरी है जरूरी की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर विशेष रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट शर्मिला डीलवार, नगर परिषद अध्यक्ष दुर्गावती वर्मा एवं उपाध्यक्ष सुरेश गायकवाड़, प्राचार्य साधना हैंड्स ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी।

सीएससी दिवस पर डिजिटल सेवाओं के सशक्तिकरण की दिखी झलक

80 से अधिक संचालकों ने साझा किए अनुभव, उत्कृष्ट कार्य के लिए किया सम्मानित

बैतूल। देश के कोने-कोने में सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के लिए बुधवार 16 जुलाई का दिन खास रहा। बैतूल में आयोजित सीएससी स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला में डिजिटल सेवाओं की ताकत और उसकी पहुंच का जीवंत चित्रण देखने को मिला। जहां एक ओर सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की गई, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संचालकों का सम्मान कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मीटिंग भवन में एक भव्य जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पानी की चोरी और पानी से छेड़छाड़ जैसी संभावित घटनाओं पर लगेगा विराम

दस सीसीटीवी कैमरों से हो रही फिल्टर प्लांट और माचना एनीकट की निगरानी

बैतूल। नगरपालिका ने माचना एनीकट पर होने वाले हर मूवमेंट और गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये है। इन कैमरों के लगने से यहां पर पानी से छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी और पानी से छेड़छाड़ की गतिविधियों पर भी विराम लगेगा। दरअसल नगरपालिका ने माचना नदी पर बने माचना एनीकट के आसपास 10 कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे नदी और घाट को कवर करेंगे। जिससे पानी की चोरी और पानी से छेड़छाड़ की घटना पर नजर रहेगी। इसके अलावा पानी की मॉनिटरिंग भी इन कैमरों से की जा सकेगी। बता दे कि शहर में रोजाना एक करोड़ लीटर पानी की सप्लाई होती है। इसके लिए माचना नदी पर 15 फीट ऊंचाई एनीकट बनाया गया है। जिसमें 10 गेट लगे है और करीब 125 करोड़ लीटर पानी रुकता है। इससे शहर में पेयजल सप्लाई की जाती है। यहां पर सीमेंट-कांक्रीट की सीढ़ियों वाला घाट भी है। घाट होने के कारण लोगों की आवाजाही भी होती है। कई बार असामाजिक तत्व और लोग यहां पर आ जाते हैं। जिससे हमेशा पानी से छेड़छाड़ और अप्रिय घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका ने सुरक्षा के लिहाज से निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये है।

माचना में मिल चुकी है लाशें

चूंकि माचना फिल्टर प्लांट से पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है और फिल्टर प्लांट का एरिया संवेदनशील भी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से निगरानी जरूरी है, क्योंकि यहां पर 2 बार लाशें मिल चुकी हैं। बायोमेडिकल वेस्टेज का बोरा भी यहां पर मिला था। यहां पर शरारती तत्व भी सक्रिय हैं, कई बार यहां पर पानी में रंग मिलाए जाने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। शाम को शराबी और असामाजिक तत्व भी कई बार यहां पर हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे में कैमरे होने से शराबी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी। खासकर पानी की सुरक्षा के लिए कैमरे आवश्यक भी थे।

खेतों की सिंचाई के लिए होता था पानी चोरी

माचना एनीकट के समीप नदी के किनारे किसानों के खेत हैं। ये कई बार नदी से सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। जलसंकट में नगरपालिका लाखापुर बांध से पानी लेती है, लेकिन इस पानी को कई बार किसान खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं। नपा कई बार मॉनिटरिंग और मोटरें हटवाने की कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी पानी चोरी पर पूरी तरह विराम नहीं लग पाया था। ऐसे में नपा अमले को नजर रखनी पड़ती है, लेकिन अब कैमरे से निगरानी होगी। जिससे पानी चोरी की घटनाएं तत्काल सामने आ जाएगी और पानी चोरी पर भी विराम लगेगा।

10 कैमरे से हो रही निगरानी

नगरपालिका ने माचना एनीकट पर 10 कैमरे लगाये है। नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि माचना फिल्टर प्लांट पर कैमरे लगाये है। जिससे कर्मचारियों के आने-जाने की मॉनिटरिंग के अलावा पानी की सुरक्षा भी हो रही है। चूंकि पेयजल सप्लाई काफी ज्यादा संवेदनशील कार्य है, इस कारण यहां कैमरे लगाए है। जिससे यहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। सबसे खास पानी के साथ छेड़छाड़ जैसे संभावित घटनाओं को लेकर यह सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि माचना एनीकट पर शवों के मिलने और बायोमेडिकल वेस्टेज का बोरा मिलने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है।

इनका कहना है -

चूंकि माचना एनीकट और फिल्टर प्लांट से शहर में पेयजल सप्लाई होती है। ऐसे में पानी के साथ संभावित छेड़छाड़ और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए नगरपालिका द्वारा 10 कैमरे लगाये गए है।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका

बैतूल में निर्मित आजीविका मिशन प्लाजा की दुकानों का पट्टा 3 साल में होगा रिनिवल

खाद की कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई, फील्ड अधिकारियों को सतत निरीक्षण के निर्देश, जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित

बैतूल। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला पंचायत एवं जनपद सदस्य सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में आजीविका मिशन प्लाजा प्रोजेक्ट पर गहन चर्चा की गई। यह प्लाजा बैतूल में निर्माणाधीन है और इसका उद्देश्य स्थानीय स्व-सहायता समूहों विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि प्लाजा में निर्मित दुकानों का पट्टा तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे हर तीन वर्ष में नवीनीकरण किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, बल्कि जिला पंचायत के लिए राजस्व का नया स्रोत भी बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवार ने आरईएस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और ठेकेदार से पूरी गुणवत्ता के साथ काम कराया जाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भवन का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वह 30 से 40 वर्षों तक मजबूती से टिका रहे और किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता जल्दी न पड़े।

सड़कों के गड्ढे भरने और स्वीकृत डेम निर्माण शुरू करने दिए निर्देश -बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवार

ने बारिश के चलते खेडी-परतवाड़ा मार्ग, मुलताई-परमंडल मार्ग के गड्ढ़ों तथा मांडवी से देहगुड़ के बीच सडक़ की साइट पटरी भरें जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए। इसके अलावा उन्होंने कोयलारी, मंजरा घोघरा और मुलताई विकासखंड में स्वीकृत डेम के निर्माण कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारी को मुलताई सहित अन्य ब्लॉकों में डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

दुकानों पर रेट लिस्ट और हेल्पलाइन नंबर चस्पा करने के निर्देश -कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीईओ श्री जैन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एसडीओ और फील्ड ऑफिसर नियमित रूप से खाद दुकानों का निरीक्षण करें।

उन्होंने कहा कि सभी खाद दुकानों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में यूरिया की रेट लिस्ट और हेल्पलाइन नंबर स्पष्ट रूप से चस्पा किए जाएं, ताकि किसानों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिक दामों में यूरिया बेचे जाने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई की जाए। सीईओ श्री जैन ने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फील्ड विजिट के दौरान किसानों से सीधा संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें योजनाओं की जानकारी दें। कृषि अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य कृषि संबंधी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई।

एक बगिया मां के नाम अभियान से ग्रामीण महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर -मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जैन ने कहा कि जिले में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की लघु और सीमांत कृषक महिलाओं को मनरेगा, उद्यानिकी एवं एसआरएलएम के समन्वित प्रयास से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण, सब्जी उत्पादन और बागवानी से जोड़ा जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने बताया कि वर्तमान में जिले भर के लगभग 2000 महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। अभियान के तहत हर ब्लॉक में 100 पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। यह चयन एक ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें हितग्राही की पात्रता लघु या सीमांत कृषक होना अनिवार्य है।

दिशा मीटिंग 17 जुलाई को

बैतूल। केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय व सांसद दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में 17 जुलाई को दोपहर 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी विभागीय अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

दक्षिण एक्सप्रेस में आधा दर्जन से ज्यादा कॉलेज छात्राएं बिना टिकट पकड़ाई

बैतूल/आमला। बुधवार को ट्रेन क्रमांक 12722 दक्षिण एक्सप्रेस में लगभग आधा दर्जन आमला कॉलेज की छात्राओं को बिना टिकट यात्रा करते हुए चेकिंग स्टाफ ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सभी कॉलेज की छात्राओं का चालान काटकर हिदायत देकर छोड़ दिया गया है।

पिछले कुछ दिनों से ट्रेन में रेलवे की तमाम सख्ती के बाद भी लगातार बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा जा रहा है, खासकर बैतूल आमला और आमला छिंदवाड़ा चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में रेलवे टीसी स्टाफ द्वारा बिना टिकट यात्रियों की पहचान की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को भी यूं तो कई बिना टिकट यात्रियों को दबोचा गया है किंतु रेलवे टीसी स्टाफ द्वारा जिस ढंग से कॉलेज की छात्राओं को भी बिना टिकट मिलने पर किसी तरह की रियायत नहीं देते हुए उनका भी चालान काटा गया है, जो रेलवे की सख्ती को उजागर करता है, साथ ही रेलवे ये संदेश भी देना चाहती है कि रेलवे के नियमों को नजरअंदाज करके यात्रा करना अब आसान नहीं होगा।

ज्यादातर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में चल रहे हैं बिना टिकट यात्री - रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आमला से बैतूल, मुलताई, पांढुर्णा, परासिया, छिंदवाड़ा की

ओर जाने वाली तमाम एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों मसलन दक्षिण एक्सप्रेस जीटी, गोंडवाना, पातालकोट और पंचवली एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में ज्यादातर बिना टिकट यात्री सफर करते हैं, रेलवे की तमाम सख्ती के बाद भी देखा जा रहा है कि बिना टिकट यात्रियों की संख्या में कोई खासी कमी नहीं आ रही है।

चेकिंग स्टाफ द्वारा प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार तक की जा रही है वसूली- इधर रेलवे के सूत्र से पता चला हैं कि आमला से प्रतिदिन इटारसी नागपुर के बीच चलने वाला चेकिंग स्टाफ, जिन की संख्या लगभग 10 होती है, सभी मिलाकर प्रतिदिन 40 से ज्यादा बिना टिकट यात्रियों को पकड़ते हैं और प्रतिदिन लगभग 35 से 40 हजार रुपए ऐसे यात्रियों से वसूल किए जाते हैं, साथ ही चेकिंग स्टाफ लगातार ऐस यात्रियों को उचित टिकट लेकर यात्रा करने की हिदायत भी दे रहे हैं।

इनका कहना है

आज हमारे पास किसी भी बिना टिकट यात्रियों का मामला नहीं बनाया गया है, वैसे ज्यादातर मामलों में चेकिंग स्टाफ मौके पर ही चालान बनाकर यात्रियों को छोड़ देता है। ऐसे हालत में जब अगर यात्री चालान का पैसा नहीं भर रहा है, तब हमारे पास मामला बनाया जाता है।

हरिओम निरंजन, थाना प्रभारी रेलवे पुलिस फोर्स आमला

ताप्ती जन्मोत्सव में सहभागिता के लिए किया सम्मानित

नगर पालिका में आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण समारोह

बैतूल/मुलताई। पवित्र नगरी मुलताई में मां ताप्ती जन्मोत्सव 2025 पुरस्कार वितरण समारोह नगर पालिका परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ मां ताप्ती की पूजा-अर्चना कर किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गडेकर ने मां ताप्ती छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष ताप्ती जन्मोत्सव में पुलिस सहित सभी स्थानीय विभाग, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका सराहनीय रही, सभी ने अपने-अपने माध्यम से मां ताप्ती का संदेश जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण ताप्ती जन्मोत्सव पर ताप्ती तट पर श्रद्धालुओं का ऐतिहासिक आगमन हुआ। वर्षा गढेकर ने

ताप्ती जन्मोत्सव में मिले सभी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ताप्ती जन्मोत्सव में विभिन्न विधाओं के प्रदर्शन एवं आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ जन प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढेकर, सभापति पार्षद गण, सीएमओ वीरेंद्र तिवारी, नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नगरवासी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने बीएलओ को दिया प्रशिक्षण

बैतूल (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री शैलेन्द्र बड़ोनियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आमला के नेतृत्व में आमला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-130 (अ.जा.) अंतर्गत बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण मतदान केन्द्र क्रमांक 98 से 197 तक के बीएलओ, सुपरवाइजर के लिए तृतीय एवं चतुर्थ बेंच के अंतर्गत आयोजित किया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री सतीष साहू, श्री दिलीप कुमार हाथिया एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री बलिराम साहू, श्री संदीप कुमार चौकीकर, श्री शैलेंद्र सूर्यवंशी एवं साहीराम मोहबे द्वारा बीएलओ को निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती रिचा कौरव, नायाब तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री श्याम बिहारी समेले की उपस्थिति रही। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री बडोनिया एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आमला द्वारा बीएलओ के कर्तव्य, संविधान की धाराएं एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित सम्पुर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा बीएलओ को निर्वाचक नामावली के त्रुटिरहित बनाने के निर्देशों में निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी प्रक्रिया, घर-घर जाकर सर्वे कर निर्वाचक की जानकारी का सत्यापन करना, मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि की जानकारी तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, बूथ लेवल एजेन्ट से समन्वय, फार्म-6, 7 व 8 एवं बीएलओ एप्प आदि के संबंध में बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण में प्रातः 9 बजे से पंजीयन कार्य, किट वितरण किया गया।

पांच चरणों में बीएलओ को दिया प्रशिक्षण : प्रथम चरण में बीएलओ को संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। द्वितीय चरण में बीएलओ की जिम्मेदारियां, रोल-प्ले, बीएलओ ऐप, वीएचए ऐप तथा फार्म-6, 6ए, 7, 8 भरने का अभ्यास कराया गया। साथ ही एसआईआर विशेष गहन परीक्षण की प्रक्रिया समझाई गई।तृतीय चरण में भरे गए फार्मों का मूल्यांकन कर त्रुटिरहित कार्य का अभ्यास कराया गया। चतुर्थ चरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध ई-मूल्यांकन लिंक के माध्यम से समस्त बीएलओ का मूल्यांकन किया गया। पांचवा चरण में बीएलओ को वीडियो क्लिप, दुविधा निवारण एवं अनुभव साझा करते हुए प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन, गणना फार्म का वितरण एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए।

कलेक्टर एंव प्रशासक सुश्री सोनिया मीना के प्रयासों से जिले की सहकारी समितियों में प्रारंभ हुआ वितरण

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर एवं प्रशासक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सुश्री सोनिया मीना के अथक प्रयासों से जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से भी खाद वितरण की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे जिले के कृषकों को बड़ी राहत मिलेगी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम के कार्यक्षेत्र जिला नर्मदापुरम से संबद्ध 99 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को विपणन संघ के जिले में संचालित 06 डबल लॉक केन्द्र कमशः नर्मदापुरम, इटारसी, माखननगर, सेमरीहरचंद सिवनीमालवा, एवं पिपरिया के माध्यम से समितियों को विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों में खाद की उपलब्धता के, अनुसार आर.ओ.डीडी पर खाद का प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया हैं। समितियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्रामों के नियमित कृषक सदस्यों को समिति के खाद वितरण केन्द्र से ही परमिट पर 0त्न ब्याज दर से खाद उपलब्ध होगा।

आधिकारी आवंटित शालाओं, स्वास्थ केन्द्रों, आंगनवाडियों आदि शासकीय संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें : कलेक्टर

● निराश्रित पशुओं को मार्गो से हटाकर शासकीय गौशालाओं एवं अस्थाई आश्रय स्थलों पर स्थानांतरित करें

नर्मदापुरम (निप्र)। सोमवार को कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक का अयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों द्वारा किये जा रहे निरीक्षण, सीएम हैल्पलाइन, समयसीमा प्रकरण, निराश्रित पशुओं को स्थानांतरित करने जैसे अन्य बिंदुओ पर विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकरियों को दिशा निर्देश दिये। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शालाओं एवं आंगनबाड़ियों तथा स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण की समीक्षा के दौरान कहा कि आगामी 1 सप्ताह में निरीक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं एवं इनपुट को संकलित कर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने परख मोबाइल ऐप पर भ्रमण एवं निरीक्षण की जानकारी अद्यतन किए जाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी अधिकारी अभियान मोड में कार्य करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष किए गए निरीक्षणों का सकारात्मक परिणाम बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने को मिला था। ऐसे में इस वर्ष भी सभी अधिकारी पूरी गंभीरता, उत्साह एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरीक्षण कार्य संपादित करें और व्यवस्थाओं को सुधारने में अपना

योगदान दें। समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की गहन समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन विभागों का निराकरण प्रतिशत कम है, संबंधित अधिकारी विशेष प्रयास कर ग्रेडिंग एवं रैंक में सुधार किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग कैंपेन मोड में कार्य करें और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता से स्वयं संपर्क कर समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों का प्रदर्शन लगातार खराब रहेगा उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कलेक्टर ने तहसील नर्मदापुरम, सिवनीमालवा, केसला, श्रम विभाग सहित सभी बी, सी अथवा डी कैटेगरी में आने वाले विभागों को निराकरण प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की रैंकिंग को बनाए रखने के लिए हर विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक रहना चाहिए, किसी एक विभाग के खराब प्रदर्शन से पूरे जिले की रैंकिंग पर विपरीत असर न पड़े। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि फोर्स क्लोज अथवा मांग में परिवर्तित करने योग्य शिकायतों का परीक्षण गंभीरता से किया जाए और केवल पूर्ण परीक्षण उपरांत ही उन्हें उक्त श्रेणियों में डाला जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अवमानना के प्रकरणों में बिना विधिक परीक्षण के कोई जवाब प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जवाब दायर करने से पूर्व शासकीय अधिवक्ता से विधिक परीक्षण अवश्य कराएं, ताकि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए की अवमानना के प्रकरणों में समय सीमा का ध्यान रखते हुए उनमें जवाब दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिले में निराश्रित पशुओं को मुख्य मार्गों और सड़कों से हटाकर शासकीय गौशालाओं एवं अस्थाई आश्रय स्थलों में भेजने की कार्यवाही की तहसीलवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में की जा रही कार्यवाहियां संतोषजनक नहीं हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आमजन के साथ-साथ पशु हानि होती है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों के समीप स्थित ग्राम पंचायतों द्वारा अस्थाई चौकीदार की व्यवस्था की जाए ताकि निराश्रित पशुओं को सड़कों पर विचरण करने से रोका जा सके और समीपस्थ गौशालाओं एवं अस्थाई आश्रय स्थलों में भेजा जा सके। साथ ही पशुओं के भूसे, चारे एवं पानी की व्यवस्था की जाए। पशुपालन विभाग भी पशुओं में होने वाली बिमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में घायल पशुओं के त्वरित उपचार की समुचित व्यवस्था हो तथा मृत पशुओं को तत्काल सड़क से हटाकर नियत स्थान पर दफनाया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्देशों का पालन समयबद्ध रूप से नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाए। कलेक्टर ने जिले में डेंगू एवं मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने के लिए घर-घर जाकर लार्वा सर्वे किए जाने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं, जनभागीदारी आदि संस्थाओं के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा जिले के अन्य दूर दराज के वन परिक्षेत्र में स्थित ग्रामों में मच्छरदानी आदि भी वितरित करवाई जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह में प्रत्येक पंचायत में डेंगू एवं मलेरिया के रोकथाम तथा बचाव संबंधी फ्लेक्स लगवाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिले में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी एवं अन्य निर्माण विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर सड़कों के गड्ढे तत्काल प्रभाव से भरे जाएं तथा अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सतत रूप से जारी रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश के मौसम में सड़कों पर जल भराव की स्थिति नहीं बने इसके लिए निर्माण एजेंसियां स्थानीय निकाय परिषदों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने सेतु विभाग को भी निर्देशित किया कि विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पुल-पुलियाओं तथा अन्य संरचनाओं की नियमित रूप से निरीक्षण एवं मरम्मत की जाए। कलेक्टर ने जिले में खाद वितरण एवं मूंग उपार्जन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि खाद वितरण के लिए समस्त उपखंड स्तरीय समिति सदस्य संपूर्ण निगरानी रखें। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि खाद्य वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए साथ ही साथ एसडीएम यह भी सुनिश्चित करें कि उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित स्कंध कि शीघ्र सिलाई एवं स्टैकिंग की जाए तथा आर टू टी में किसी भी प्रकार का विलंब ना हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी केंद्र पर किसी भी प्रकार की अनियमिता पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर एंव प्रशासक सुश्री सोनिया मीना के प्रयासों से जिले की सहकारी समितियों में प्रारंभ हुआ वितरण

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर एवं प्रशासक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सुश्री सोनिया मीना के अथक प्रयासों से जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से भी खाद वितरण की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे जिले के कृषकों को बड़ी राहत मिलेगी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम के कार्यक्षेत्र जिला नर्मदापुरम से संबद्ध 99 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को विपणन संघ के जिले में संचालित 06 डबल लॉक केन्द्र कमशः नर्मदापुरम, इटारसी, माखननगर, सेमरीहरचंद सिवनीमालवा, एवं पिपरिया के माध्यम से समितियों को विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों में खाद की उपलब्धता के, अनुसार आर.ओ.डीडी पर खाद का प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया हैं। समितियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्रामों के नियमित कृषक सदस्यों को समिति के खाद वितरण केन्द्र से ही परमिट पर 0त्न ब्याज दर से खाद उपलब्ध होगा।

राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। बगैर सर्वे, बगैर तैयारी, आरक्षण देने की बात करके फैलाए गए भ्रम के कारण यह मामला कोर्ट में लंबित रहा।

सभी कलेक्टर्स सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं की समस्या का समुचित निदान करें : कमिश्नर

सभी ओवरफ्लो पूल पूलियो और रपटों पर संकेतक लगाकर बैरिकेडिंग की जाए

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदापुरम संभाग के हरदा बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिले में सड़कों पर विचरण करने वाले एवं सड़कों पर बैठने वाले निराश्रित पशुओं से होने वाली समस्याओं का समुचित निदान करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि निराश्रित पशुओं के पुनर्वास के लिए उन्हें नजदीक के गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि नर्मदापुरम के बाबई एवं हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं के विचरण करने की एवं सड़कों पर बैठने की समस्याएं लगातार सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह उक्त समस्याओं का प्राथमिकता से निदान करें। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह बारिश के दौरान लगातार अपने प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर रखें। नर्मदापुरम एवं हरदा में नर्मदा नदी एवं बैतूल में सापना जलाशय से बाढ़ की संभावना बन सकती है। इसको देखते हुए सभी बचाव के आवश्यक उपाय अभी से सुनिश्चित किए जाएं।

कमिश्नर ने निर्देश दिए कि लगातार बारिश के दौरान यदि कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो पीड़ित को तत्काल राहत राशि देना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बारिश के दौरान डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए भी सभी आवश्यक दवाईयां एवं उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि बारिश के दौरान कोई जन हानी ना हो इसके लिए नर्मदा नदी के किनारे के रहने वाले लोगों को लगातार जागरूक किया जाए सभी ओवरफ्लो पूल पुलियों, रपटों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। वहां बैरिकेडिंग की जाए और चौकीदार की व्यवस्था भी की जाए। होमगार्ड की टीम पूरे समय सतर्क रहकर स्थिति पर नजर रखें।

कमिश्नर ने निर्देश दिए की चिन्हित सभी जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करने की कार्रवाई भी की जाए। कमिश्नर श्री तिवारी ने नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना को निर्देश दिए की वह हिल स्टेशन पचमढ़ी में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाएं। कमिश्नर ने कहा कि पचमढ़ी बस स्टैंड एवं पचमढ़ी के मार्गों पर लगातार वाहनों का जाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने इन सब के लिए प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर श्री तिवारी ने महादेव मंदिर जाने वाली सड़क की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने ई ऑफिस सिस्टम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संभाग एवं जिला स्तर पर एनआईसी के किसी टेक्निकल व्यक्ति को नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहदान और अंगदान करने वाले नागरिकों के परिजनों को 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सम्मानित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि हृदय, लीवर एवं किडनी दान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिले में देहदान एवं अंगदान करने वाले नागरिकों के परिजनों को चिन्हित कर ले। कमिश्नर ने शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर तथा कुपोषण में सुधार की अदयतन स्थिति की समीक्षा की तथा जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए की आगामी सप्ताह में हरदा बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले में हर घर नल कनेक्शन में अपेक्षित प्रगति दिखे। उन्होंने राजस्व संग्रहण, राजस्व अभिलेख एवं आरसीएमएस पोर्टल पर रीडर एवं पीठासीन अधिकारी की आईडी पर लंबित प्रकरणो का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए तथा निर्देश दिए की फसल गिरदावरी में श्री अन्न एवं उद्यानिकी फसलों की भी गिरदावरी की जाए। कमिश्नर श्री तिवारी ने आगामी सप्ताह में नागद्वारी एवं अन्य पर्व एवं त्योहार के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए की किसानों को उर्वरक की कोई कमी ना हो और खाद वितरण भी व्यवस्थित रूप से किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ऑनलाइन एवं उपायुक्त राजस्व श्री गणेश जायसवाल तथा संयुक्त आयुक्त विकास श्री जी सी दोहर ऑफलाइन उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक मे कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने बैठक में उपस्थित विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से कर्मचारियों के हित में अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभाग के कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से उनकी मांग एवं समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अनेक संघों के पदाधिकारियों ने जिले में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, लंबित एरियर्स की मांग, सेवा पुस्तिका का समय पर संधारण, सेवानिवृति उपरान्त शीघ्र स्वत्वों का भुगतान सहित अपनी अन्य मांगें रखी। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने

कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के सभी मांग, समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना और निराकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभाग के अधिकारियों को लंबित एरियर्स के प्रकरण को नियमानुसार कार्रवाई कर समयावधि में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरण के आवेदन लंबित हैं उन्हें भी प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया तथा संबंधित विभागों को समय अवधि में कर्मचारियों के मांग को आवश्यक कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाति मिश्रा, अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष श्री बंशीलाल धनवाल, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह ठाकुर, लिपिक वर्ग मध्यप्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह, वन विभाग अध्यक्ष श्री चेतन कुमार आर्य, अपाक्स अध्यक्ष श्री कमल कीर, आजाद अध्यापक संघ जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रांतीय शिक्षक संघ श्री संजय सक्सेना सहित अनेक अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरते : सीईओ

बैतूल (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं, समसामयिक मुद्दों की गहन समीक्षा की। सीईओ श्री जैन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं में निर्धारित समयावधि में प्रगति सुनिश्चित करें और शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ श्री जैन ने कहा कि जिले में यूरिया की आपूर्ति एवं वितरण को लेकर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसको लेकर किसी भी प्रकार का चक्का जाम, प्रदर्शन अथवा जन-अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम एवं तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें एवं संभावित परिस्थितियों की समीक्षा करें। ब्लॉक कृषि अधिकारी संबंधित एसडीएम को प्रतिदिन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, जिससे प्रशासन को वस्तुस्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

सभी अधिकारी फील्ड वर्क पर जाए, जनता से करें संवाद

सीईओ श्री जैन ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा कर शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश सभी विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि 50 दिवस से अधिक की शिकायतों के निराकरण पर भी सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी फील्ड वर्क पर जाए और जनता से संवाद कर शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। कोई भी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरते। उन्होंने जल संसाधन, उद्यानिकी विभाग, पीडब्ल्यूडी, श्रम, राजस्व, ट्राइबल, वन विभाग, पीएचई विभाग के शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। सीईओ श्री जैन ने समग्र ईकेवाईसी की विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रत्येक निकाय और जनपद को लक्ष्य के विरुद्ध ई केवाईसी कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. बने निक्षय मित्र, पांच टीबी मरीजों को लिया गोद

सीहोर (निप्र)। टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी अभियान के तहत कलेक्टर श्री बालागुरू के ने निक्षय मित्र के रूप में अपना पंजीयन कराकर पांच टीबी मरीजों की पोषण आहार सहायता की जिम्मेदारी ली। गोद लिए गए इन टीबी मरीजों को 06 माह की उपचार अवधि तक प्रतिमाह फूड बास्केट दिया जायेगा। कलेक्टर तथा जिला पंचायत सीईओ सहित 47 अधिकारियों ने टीबी मरीजों को गोद लिया है। टीबी मरीजों को दिये जाने वाले फूड बास्केट में हाई प्रोटीन डाइट उपलब्ध है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा है कि टीबी रोग को हराने और देश को जिताने के साथ ही सीहोर जिले को टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग और प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्षय उन्मूलन के लिए सभी समर्थ नागरिक इस जनभागीदारी कार्यक्रम से जुड़ सकते है। क्षय उन्मूलन के लिए सीहोर जिले में प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों

और नागरिकों से इस कार्यक्रम में अपनी स्वैच्छिक सहभागिता देने के अपील की है। क्षय रोगियों को दिये जाने वाले फूड बास्केट में हाई प्रोटीन डाइट उपलब्ध है। उन्होंने क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीहोर को क्षयमुक्त बनाने के लिए समय-समय पर समाज के सक्षम नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं से स्वैच्छिक रूप से फूड बास्केट सहयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री नितिन टाले, श्री जमील खान, श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाती मिश्रा, श्री सुधीर कुशवाह, सीएमएचओ श्री सुधीर डेहरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

फूड बास्केट देने स्वयं जाएं अधिकारी

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी अधिकारियों से कहा कि उन्होंने जिन टीबी मरीजों को गोद लिया है, उन्हें फूड बास्केट देने स्वयं जाएं। स्वयं टीबी मरीज से मिलने पर वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकेंगे और उसके स्वास्थ्य में आ रहे बदलाव को देख सकेंगे। अधिकारी स्वयं टीबी मरीज के परिजनों और मरीज को जल्द स्वस्थ होने के लिए पोषण आहार सहयोग के साथ ही जागरूक भी कर सकेंगे।

उज्जैन में खाप पंचायत जैसा फैसला पुजारी का बहिष्कार किया

तीन बच्चों को स्कूल से निकाला, पूजा कराने, बाल काटने, मजदूरी करने पर भी रोक

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के झलारिया पीर गांव में खाप पंचायत जैसी सामाजिक बैठक में मंदिर के पुजारी और उनके परिवार पर बहिष्कार कर दिया गया। उसके बच्चों की पढ़ाई से लेकर पूजा, कटिंग और मजदूरी तक पर रोक लगा दी गई। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने वालों पर 51 हजार रुपए जुर्माने की चेतावनी दी गई है। गांव के नागराज मंदिर परिसर में ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दूसरी ग्राम पंचायत के सचिव गोकुल सिंह देवड़ा ने पंचायत का फैसला माइक पर पढ़कर सुनाया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने हाथ उठाकर सहमति जताई। एक व्यक्ति ने बच्चों को स्कूल से निकलवाने के निर्णय का विरोध किया। इस पर पंचायत ने कहा कि कुछ लोगों का सुझाव आया था, बच्चों को स्कूल से बाहर करवा दें, इसलिए इसे फैसले में शामिल किया है। इस घटना के बाद

पुजारी पूनमचंद चौधरी ने कलेक्टर से शिकायत की है, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। गोकुल सिंह देवड़ा ने फैसला पढ़ा। ग्रामीणों ने हाथ उठाकर सहमति दी। गोकुल दूसरी ग्राम पंचायत का सचिव है। गोकुल सिंह देवड़ा ने फैसला पढ़ा। ग्रामीणों ने हाथ उठाकर सहमति दी। गोकुल दूसरी ग्राम पंचायत का सचिव है।

मंदिर की जमीन और पुजारी को हटाने का विवाद- करीब 4 हजार की आबादी वाले झलारिया पीर गांव में देव धर्मराज मंदिर की देखरेख पूनमचंद चौधरी का परिवार वर्षों से करता आ रहा है। मंदिर से लगी करीब 4 बीघा जमीन पर पुजारी खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार के मुताबिक कुछ ग्रामीण मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसी राशि से मंदिर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका पुजारी परिवार ने विरोध किया। पुजारी के बेटे मुकेश चौधरी ने बताया कि विरोध के बाद उन्हें और परिवार को निशाना बनाकर गांव के प्रभावशाली लोगों ने 14 जुलाई को पंचायत बुलाकर बहिष्कार का फरमान सुना दिया।

इंदौर-खंडवा रेल लाइन को मिली वन विभाग की एनओसी

उत्तर-दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा रेल मार्ग बनेगा

इंदौर (नप्र)। इंदौर-खंडवा रेल परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। वन विभाग ने इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी कर दिया है। जिससे अब इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह रेल लाइन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा रेल मार्ग साबित होगी, जो न केवल इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक भविष्य को नई रफ्तार देगा, बल्कि यात्रियों को भी समय और दूरी दोनों में राहत देगी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इस प्रोजेक्ट में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार

प्रयास किए हैं। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और वन विभाग के बीच संयुक्त बैठक करवाई थी, जिससे आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हुईं। इसके बाद हाल ही में सांसद लालवानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इस परियोजना की प्राथमिकता को रेखांकित किया और वन विभाग से अनुमति दिलवाने का अनुरोध किया था। इंदौर-खंडवा रेल लाइन के पूरा होने के बाद इंदौर का संपर्क सीधे खंडवा-भुसावल-नासिक-मुंबई की ओर तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों से तेज़, किफायती और सुविधाजनक सफर हो जाएगा। इस रेल कॉरिडोर से मालवांचल के व्यापारियों, किसानों और यात्रियों सभी को लाभ मिलेगा। सांसद ने बताया कि यह रेल मार्ग मालवांचल और दक्षिण भारत के बीच सीधी व बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम है।

देश के सबसे साफ शहरों में भोपाल दूसरा

स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में बढ़ा आगे, एक साल में 3 पायदान छलांग लगाई

भोपाल (नप्र)। स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में भोपाल देश के सबसे साफ शहरों में टॉप-3 पर है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया, भोपाल ने 3 पायदान छलांग लगाई है और देश में दूसरी रैंकिंग मिली है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू पुरस्कार देगी।

6 साल बाद भोपाल दूसरे नंबर पर आएगा। इसलिए जश्न भी भव्य तरीके से करेंगे। स्वच्छता मित्रों और जनता के साथ जश्न मनाएंगे। लड्डू भी बांटे जाएंगे। गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता कार्यक्रम होगा। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू शामिल होंगी।

पिछली बार पांचवें नंबर पर था भोपाल- पिछले सर्वे में भोपाल 5वें नंबर पर था। कचरे की प्रोसेसिंग में सुधार और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को और पुख्ता कर भोपाल ने दावा मजबूत किया है। वहीं, फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की वजह से भी भोपाल को फायदा मिलेगा। जीआईएस के चलते राजधानी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम शहर में हुए हैं। इसमें स्वच्छता से जुड़े काम भी शामिल थे। इसी दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें भी भोपाल पहुंची थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल का अब तक का सफर

● स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने 2017 और 2018 में लगातार दो साल देश में दूसरी रैंक हासिल की थी। ● 2019 में भोपाल खिसककर 19वें नंबर पर आ गया। उस समय अफसरों के लगातार तबादले के कारण तैयारियों की दिशा ही तय नहीं हो पाई थी। ● 2020 में कम बैक करते हुए 12 पायदान ऊपर खिसका और 7वीं रैंक हासिल की। ● 2021 के सर्वेक्षण में भी भोपाल ने 7वां स्थान हासिल किया था। ● 2022 के सर्वेक्षण में भोपाल की रैंक सुधरी और यह छठवें स्थान पर आ गया। वहीं, भोपाल को 5 स्टार मिले थे। ● 2023 के सर्वेक्षण में पांचवीं रैंकिंग रही थी। ● सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा मिलने की उम्मीद ● स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार भी मध्यप्रदेश के शहर बाजी मारेंगे। राजधानी भोपाल देश के सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरे नंबर पर रहेगा। साथ ही सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा भी फिर मिलने की उम्मीद है।

मैड्रिड से मप्र तक खेल से खुली निवेश की नई राह: मुख्यमंत्री

● म.प्र. में पीपीपी मोड पर फुटबाल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पेनिश कोचिंग आधारित प्रारंभ होंगे यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम: सीएम

डॉ. यादव ने किया ला-लिगा मुख्यालय का भ्रमण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरूआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध ला-लीगा मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया।

उन्होंने कहा कि ला-लिगा की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुँच का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं तक पहुँचना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार, सामाजिक समावेशन

और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लालीगा के पदाधिकारी और तकनीकी निदेशकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्पेनिश कोचिंग आधारित यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि लालीगा के साथ यह साझेदारी केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, सामाजिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दे सकती है।

लालीगा मैचों में होगी म.प्र. की ब्रांडिंग

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुझाव दिया कि लालीगा मैचों के दौरान डिजिटल और ग्राउंड को-ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, वन्यजीव, विरासत स्थलों और पर्यटन अवसरों का स्पेन और यूरोप के व्यापक दर्शकों के बीच प्रभावी प्रचार किया जा सकता है।

राज्यपाल पटेल से मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति सचदेवा ने की भेंट

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल का उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने मनोनीत न्यायमूर्ति श्री सचदेवा का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति श्री सचदेवा के परिजन भी उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पेन के मैड्रिड स्थित ला-लीगा मुख्यालय पहुँचकर वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की।

● मापदंड अनुसार ब्रिज परियोजनाओं के डिजाइन और गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग संकल्पित

किसी भी कार्य की जीएडी निरस्त नहीं की गयी

भोपाल (नप्र)। ब्रिज परियोजनाओं का तकनीकी मापदंडों के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक व्यापक दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी अभियंताओं को इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) कोड्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ (मोर्थ) के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर उनके आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्रिज परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मापदंड अनुसार डिजाइन, सतत सुपरविजन प्रणाली अपनाने एवं निर्माण के दौरान सतत निरीक्षण के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रेलवे अथवा नगर निगम जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।

मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र श्री पीसी वर्मा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पुराने अलाइनमेंट्स को रद्द नहीं किया गया है अपितु गलती से जारी हुआ एक त्रुटिपूर्ण आदेश उसी दिन निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पुलों और फ्लायओवर की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) रेलवे और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती हैं। मुख्य अभियंता को इन्हें निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी कोई आवश्यकता किसी परियोजना में परिलक्षित नहीं हुई है। निर्माण कार्यों के दौरान अक्सर स्थान विशेष की परिस्थिति अनुसार अलाइनमेंट और डिजाइन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो कि सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे परिवर्तनों के दौरान संबंधित आईआरसी कोड और मोर्थ के मापदंडों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है।

राज्य शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्माण के दौरान होने वाले सभी परिवर्तन अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे नगर निगम और रेलवे के समन्वय से ही किए जाएं। परियोजनाओं के रुकने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

रेप का आरोप लगा तो ट्रेन के सामने कूदा

दतिया में शव रखकर चक्काजाम, पथराव

दतिया (नप्र)। ग्वालियर के डबरा में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। उस पर कुछ घंटे पहले ही रेप का केस दर्ज हुआ था। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे- 44 के बड़ोकलां तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए, लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

घटना मंगलवार की है। गोराघाट के ग्राम पचोखरा के रहने वाले 21 साल के आकाश रावत पर दोपहर करीब 2.30 बजे एक युवती ने गोराघाट थाने में रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस आकाश को पकड़ने डबरा पहुंची, लेकिन वह फरार हो गया। कुछ ही देर बाद उसने सिमरिया टेकरी के पास ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी।

मौत से पहले परिजन को कॉल किया- परिजनों के अनुसार, सुसाइड से पहले आकाश ने अपने ताऊ महेंद्र सिंह रावत को कॉल किया था। उसने कहा था- पुलिस पीछा कर रही है, मैं रेलवे ट्रैक की तरफ भाग रहा हूं। परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आकाश की मौत हो चुकी थी।

युवती के परिजन कर रहे थे पैसों की मांग- आकाश के ताऊ महेंद्र सिंह रावत ने बताया, रविवार को गांव की युवती घर से चली गई थी। उसके परिजन ने आकाश पर उसे भगाने का आरोप लगाकर गोराघाट थाने में शिकायत की थी। सोमवार को थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया और समझौते की कोशिश की गई।

युवती के परिजन ने समझौते के एवज में 15 से 20 लाख रुपए की मांग की। आकाश के परिवार ने 10 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके बाद आकाश मानसिक तनाव में आ गया। मंगलवार को उसने सुसाइड कर लिया।

शव रखकर चक्काजाम, पुलिस पर पथराव- मंगलवार देर रात परिजन आकाश का शव लेकर नेशनल हाईवे पहुंचे और बड़ोंकलां तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। करीब ढाई घंटे तक हाईवे पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जब जाम खोलने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस के वाहन और कुछ राहगीरों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

सरेराह युवक पर जानलेवा हमला

छुरी-तलवार से वार किए, बदमाशों ने घायल का वीडियो पोस्ट कर लिखा-...और करो उलझन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गैमन इंडिया मॉल के पास मंगलवार-बुधवार रात के बीच एक मैकेनिक पर बदमाशों ने सरेराह जानलेवा हमला कर दिया। हथियारों से लैस करीब आधा दर्जन बदमाश कार से पहुंचे और युवक पर छुरी-तलवार से ताबड़तोड़ वार किए। हमले के पीछे वजह अड़ीबाजी की रकम न देना बताया जा रहा है।

घायल अमन (22), जो टीटी नगर के शिव नगर कॉलोनी में रहता है, को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके दाहिने हाथ की तीन उंगलियों में गहरे कट हैं, कंधे और जांघ में भी गंभीर चोटें आई हैं। आज उसके हाथ की सर्जरी की जानी है।

पैसे नहीं दिए तो मार देंगे- पीड़ित के भाई फैजान के अनुसार, इलाके के बदमाश नरेंद्र रायकवार और नीलेश

रजक बीते कई महीनों से अमन पर अड़ीबाजी कर रहे थे। धमकी दी जाती थी हर महीने तय रकम दो, वरना दुकान बंद करवा देंगे। अमन टीटी नगर क्षेत्र में मैकेनिक की दुकान चलाता है। डर के चलते उसने कई बार पैसों की मांग पूरी भी की, लेकिन जब लगातार परेशान किया गया, तो उसने तीन महीने पहले थाने में शिकायती आवेदन दिया था। हालांकि, पुलिस ने उस वक्त कोई एफआईआर दर्ज नहीं की।

इनोवा से आए और हमला किया- वारदात मंगलवार देर रात 2:30 बजे की है। अमन मॉल के पास चाय की दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी नरेंद्र, नीलेश और उनके 3-4 साथी इनोवा कार में पहुंचे। सभी के पास धारदार हथियार थे। उन्होंने बिना कुछ कहे हमला कर दिया। अमन के चीखने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।

घायल अमन का वीडियो अपलोड किया- हमले के कुछ देर बाद आरोपी नरेंद्र रायकवार ने अमन की हालत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा और करो उलझन।